सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
भोपाल
शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 170, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

04 - गलगोटिया का कुत्ता लांछित भारत की एआई सत्ता

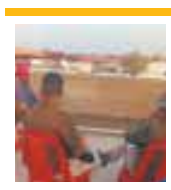

05 - जीवन कौशल शिक्षा : आत्मबल की पाठशाला

06 - धूमधाम से मनाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती

07 - कुबेरेश्वर धाम में व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखने के निर्देश...

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

महंगाई मापने का नया सूचकांक, बदलाव का खामोश पक्ष क्या?

अरविंद मोहन

भारत में महंगाई मापने के नए सूचकांक के प्रभाव क्या हैं? सिर्फ आँकड़ों में बदलाव नहीं बल्कि रोज़मर्रा खर्च, जीवन स्तर और आर्थिक निर्णयों पर इसका खामोश प्रभाव भी अहम है। अब 1.8 फीसदी कोई ऐसा संकेत नहीं है कि डर के मारे हम शोर मचाने लगें कि महंगाई जान मार रही है और सरकार को तुरन्त कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। महंगाई के मोर्चे पर सरकार लगातार सक्रिय भी रही है। बल्कि कई बार हम उसकी सक्रियता को लेकर ही यह सवाल उठाते रहे हैं कि उसे सिर्फ उपभोक्ताओं की चिंता है, उत्पादकों, खासकर, किसानों की नहीं। आखिर उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से कम है और चुनावी राजनीति में गिनती का बहुत महत्व है। पर आँकड़े के इतने पर आते ही दसेक महीने का रिकॉर्ड अर्थात थोक मूल्यों में साल के सबसे अधिक स्तर पर आने की सूचना मिले तो कान खड़े होने ही चाहिए। इसकी वजह महंगाई नहीं, उसको मापने का पैमाना बनाया जाना चाहिए। अपने निजी अनुभव से हमें महंगाई बढ़ने का ही एहसास होता है। लेकिन जब भी उससे संबंधित आँकड़े आते हैं, वे उलटी तस्वीर पेश करते थे। हम मन मसोस कर रह जाते थे।

उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार द्वारा जारी नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लागू होने के बाद से ऐसा कम होगा और जनवरी 2026 के आँकड़े इस दिशा में संकेत करने भी लगे हैं। जनवरी में यह 2.75 फीसदी आया। थोक मूल्य सूचकांक एकदम अलग आधार पर चलता है लेकिन उसमें भी बढ़ोत्तरी का मतलब बाजार का गरमाना ही है। खाद्य पदार्थों और फल-सब्जी की महंगाई हम वैसे भी झट से अनुभव करने लगते हैं। पर चर्चा महंगाई पर नहीं, सूचकांक पर करनी चाहिए और इस बदलाव का स्वागत होना चाहिए।

असल में सूचकांक शहरी उपभोक्ताओं के लिए होता है और उससे भी ज़्यादा सरकारी और संगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिए होता है जिन्हें इस सूचकांक के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलता है। देश की बड़ी और बाक़ी आबादी के लिए यह एक सूचना भर है तो सरकार के लिए ख़तरे की घंटी। उसे जैसे ही महंगाई की भनक लगती है वह सक्रिय हो जाती है। पर दिलचस्प तथ्य यह भी है कि कई बार सरकारी फ़ैसलों के चलते भी महंगाई आती है। और अक्सर प्रशासनिक असफलता मुनाफाखोरों के लिए लूट का रास्ता बनाती है।

हमारी खान पान और जीवन शैली के बदलाव के चलते समय समय पर सूचकांक में बदलाव लाना जरूरी हो जाता है। एक आम शहरी वेतनभोगी के जीवन में जिन वस्तुओं और सेवाओं की जितनी और जैसी ज़रूरत होती है, उसका एक भारांक सूचकांक में तय किया जाता है। फिर उनके चालू बाजार मूल्य को उठाकर पूरा सूचकांक बनता है, जिसका चढ़ना गिरना महंगाई की सही तस्वीर देता है। यह नहीं हो सकता कि चावल और गेहूं का भारांक वही हो जो नमक का होगा।

मकान किराया, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, परिवहन का खर्च, मनोरंजन, दूध-दही, मांस-मछली, फल-सब्जी अगर खर्च के बड़े आइटम होते हैं तो उन्हें सूचकांक में भी वही महत्व देने की कोशिश की जाती है। लेकिन बदलाव तो जीवन का नियम है। जैसे इस बार सूचकांक से डीवीडी, कैसेट और वीसीआर को निकाल दिया गया है तो ओटीटी सब्सक्रिप्शन के खर्च को जोड़ लिया गया है। कभी ईंधन के रूप में कोयला और लकड़ी का वजन काफी था तो आज गैस ने उसकी जगह ली है। खाने पीने के आइटमों में तो और बदलाव आ गया है। जाहिर तौर पर 2024 के मूल्यों को आधार बनाने वाले इस बार के नए सूचकांक में इन बदलाओं को समेटने की कोशिश हुई है।

लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है और जो जल्दी ही खुदरा मूल्य सूचकांक के उतार-चढ़ाव को प्रभावित करेगा, वह है मुफ़्त राशन योजना में मिलने वाले आइटमों को सूचकांक की गणना से बाहर रखने का। विकसित देशों में ऐसा लाभ पाने वालों की संख्या पाँच से दस फीसदी तक हुआ करती है जबकि अपने यहां राजनैतिक वजहों से 75 फीसदी ग्रामीण आबादी और पचास फीसदी शहरी आबादी मुफ़्त अनाज योजना से कवर होती है तो कई तरह के सामान (मुफ्त बिजली, पानी, साइकिल, लैपटाप, टीवी, सोना वगैरह) और सेवाओं का लाभ उससे भी ज्यादा लोग पाते हैं। जिस कमेटी ने नए सूचकांक को आखिरी रूप दिया उसके सभी 22 सदस्य इन सभी की गिनती को सूचकांक के दायरे से बाहर ले जाने के पक्ष में थे। पर कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि खाद्यान्न के बाजार मूल्य और राशन मूल्य का औसत लेने से सूचकांक ज्यादा अच्छी और सच्ची तस्वीर देगा।

सूचकांक में 2012 वाली श्रृंखला के 299 आइटमों की जगह 350 आइटम शामिल किए गए हैं, जो इस अवधि में हुए बदलाव को संभालने का प्रयास है। जैसा पहले बताया गया है कि कई चीजों का भारांक (वेटेज) भी बदला है। लेकिन जानकार मानते हैं कि अभी कई चीजों की गिनती ही नहीं हुई है या भारांक गलत बताए गए हैं जिससे सूचकांक पूरी तरह सही तस्वीर नहीं देगा।

इनमें नगर परिवहन में काफी प्रभावी हो चुके मेट्रो के भाड़े को शामिल न करना एक प्रमुख चूक है। साइकल रिक्शा और तांगे के किराए को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है जब मेट्रो और इ-रिक्सा जैसे सबसे ज्यादा उपभोग में आने वाले साधनों को छोड़ दिया गया है। ऐप आधारित परिवहन सेवा को शामिल करना सही फैसला है तो ग्रामीण इलाकों में भी मकान भाड़ा का हिसाब सूचकांक के दायरे में लाना एक जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है। आज गांवों में भी भाड़े पर मकान लेकर रहने का चलन कम है लेकिन शुरू हो गया है। शहरी जीवन में बाहर भोजन करना भी एक जरूरी खर्च बनता गया है।

इस बार के सूचकांक में इलाज और शिक्षा पर खर्च का भारांक बढ़ा, यही है जो वास्तविकता के करीब है। अब इसमें यह भेद सूचकांक के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता है। दोनों में खर्च बढ़ाने की मुख्य वजह यहां निजी क्षेत्र का जोर बढ़ाना और सरकार का यहां से हाथ खींचते जाना है। यह विषय सूचकांक तय करने वालों से अलग है। कपड़े लत्ते के खर्च को भी ज्यादा वेटेज दिया गया है जो सही है। लेकिन इस बार भोजन वाले कुल आइटमों का भारांक काफी गिरा है। अब बाहरी दिखावों, सामाजिक आयोजनों और परिवहन के खर्च बढ़ाने का मतलब उस परिवार की सामाजिक आर्थिक हैसियत का बढ़ाना भी होता है, जबकि गरीब के बजट का ज्यादा से ज्यादा बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है। इस बदलाव का यह एक खामोश पक्ष है, लेकिन बताने के लिए ज़रूरी भी है। इससे सरकार, सूचकांक बनाने वालों और बाजार चलाने वालों की सोच की दिशा का पता चलता है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

फ्री-खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे?

● सुप्रीम कोर्ट बोला- सरकारें मुफ्त की चीजों के बजाय लोगों को रोजगार दें

कहा- मुफ्त बिजली-पानी देने से काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फ्रीबीज कल्चर (मुफ्त की रेवड़ियां) पर कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि देश के ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में हैं और फिर भी वे विकास को नजरअंदाज करते हुए मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं। आपको लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बनाने चाहिए, ताकि वे कमा सकें और अपनी इज्जत और आत्म सम्मान बनाए रख सकें।

● **अचानक चुनाव के आस-पास स्कीम क्यों अनाउंस की जाती हैं-** अब समय आ गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, नेता फिर से सोचें। अगर हम इस तरह से उदारता दिखाते रहे तो हम देश के डेवलपमेंट में रुकावट डालेंगे। एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा। यह समझ में आता है कि कल्याणकारी योजना के तहत आप उन लोगों को राहत दें, जो बिजली का बिल नहीं चुका सकते। जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं और जो नहीं हैं, उनके बीच कोई फर्क किए बिना मुफ्त सुविधा देना क्या तुष्टीकरण की नीति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु की सुनवाई कर रहा था।

असम में आसान नहीं होगी कांग्रेस की राह

बीजेपी ने किया 'खेला', सेट किया 18 फीसदी का टारगेट

दिसपुर (एजेंसी)। असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा के लिए यहां सत्ता बचाने की चुनौती है। भगवा खेमा अगर यहां सरकार बनाने में सफल होता है तो असम में यह हैट्रिक होगी। भाजपा ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को असम विधानसभा में 50 फीसदी वोट लाने का लक्ष्य दिया है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में में बीजेपी का वोट शेयर 33.2 फीसदी था। वहीं, सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस को उस समय जबरदस्त झटका लगा जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी। भाजपा अध्यक्ष के द्वारा दिए गए टारगेट को अगर बीजेपी हासिल कर लेती है तो सभी दलों का सूपड़ा साफ कर देगी। विपक्ष सिर्फ 20-28 सीटों पर सिमट जाएगा। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की लोकप्रियता अभी भी कायम है। कांग्रेस की बात करें तो असम विधानसभा की राह आसान नहीं है। वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा के इस्तीफे से जहां पार्टी आंतरिक चुनौती से जूझ रही है, वहीं महाजोत में भी सब कुछ ठीक नहीं है। सीट बंटवारे में ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने को लेकर महाजोत के कई घटकदल दबाव बनाए हुए हैं। असम में अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस असम में एकजुट नहीं है।

मप्र में नवकरणीय ऊर्जा विकास के लिए सिकोया क्लाइमेट फाउंडेशन के साथ हुआ एमओयू, मुंबई क्लाइमेट वीक-2026 में की सहभागिता

क्लाइमेट चेंज से निपटने में लीडर बन रहा है मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज एक गंभीर वैश्विक चुनौती है। क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व, आर्थिक स्थिरता और भावी पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि सतत् विकास की राह में हम पर्यावरण की अनदेखी नहीं कर सकते। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना ही प्रगति का मूल आधार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जोर देकर कहा कि क्लाइमेट चेंज के मामले में ठोस और समयबद्ध समाधान पर काम करना आज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत की क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रतिबद्धताओं में भी राज्यों का योगदान भी महत्वपूर्ण है।

मध्यप्रदेश क्लाइमेट चेंज से निपटने में सर्वाधिक नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादक बन लीडर की भूमिका में है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में अग्रणी है। यहां लगभग हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। मुख्यमंत्री ने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मप्र में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को हरसंभव सहयोग देने का विश्वास और सुरक्षा की गारंटी देते हुए कहा कि राज्य और निवेशक मिलकर देश को नवकरणीय ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली देने की दिशा में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। निवेशकों के साथ हमारा रिश्ता नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार-व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार की शाम मुंबई में क्लाइमेट वीक-2026 को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मध्यप्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग (मप्र शासन) एवं ग्रीन एनर्जी के लिए विख्यात सिकोया क्लाइमेट फाउंडेशन के बीच मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में एमओयू हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान केवल एक देश, एक राज्य या एक सरकार ही नहीं कर सकती, इसके लिए राष्टीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन, हरित विकास और जलवायु समाधान के लिए आगे बढ़ने की दिशा में मुम्बई क्लाइमेट वीक एक महत्वपूर्ण मंच है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए त्वरित और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के स्वच्छ स्त्रोतों को बढ़ावा देना, हरित तकनीकों को अपनाना और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करना ही भविष्य का विकास मार्ग है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पृथ्वी को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकारों के साथ ही उद्योगों, संस्थाओं और इस देश में रहने वाले हर नागरिक की भी है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए 'लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट' जैसे व्यवहारिक बदलावों को अपनाने की अपील की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हरित ऊर्जा उत्पादन के जरिए क्लाइमेट चेंज से निपटने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार के नवाचारों की जानकारी देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश भारत के उन अग्रणी राज्यों में से एक है, जिसने नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है।

शरद की सुबह

ज़हर से ज़हर कटे
काँटे से किरची निकले
दे नया दर्द कि ये
टीस पुरानी निकले
ज़िंदगी यूँ तो नया लफ़्ज़
नहीं है लेकिन
वक़्त के साथ नए
इसके म'आनी निकले
क्यूँ कोई कोख जो सूनी
हो वो शर्मिंदा हो
क्या ज़रूरी है कि हर
सीप से मोती निकले
इश्क़ की झील में उतरो
तो सँभल कर उतरो
ऐन मुमकिन है ये
उम्मीद से गहरी निकले
एक वो शख़्स जिसे
दिल ने ख़ुदा जाना हो
सोचिए क्या हो अगर
वो भी फ़रेबी निकले
छटपटाते हैं उदासी से
निकलने को मगर
क़ैद-ए-सय्याद से
कैसे कोई पँछी निकले
वो तरीक़ा मुझे मरने का
बताओ जिस से
ख़ुदकुशी भी न लगे
जान भी जल्दी निकले

विभा जैन ख़्वाब

डीपफेक रोकने के लिए एआई कंटेंट पर लेबल लगे

पीएम बोले-एआई में भय नहीं 'भाग्य' और भविष्य है

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के सुरक्षित इस्तेमाल का नया फॉर्मूला दिया। पीएम ने कहा कि जैसे खाने के पैकेट पर 'न्यूट्रिशन लेबल' होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी 'ऑथेंटिसिटी लेबल' होना चाहिए ताकि फर्क पता चल सके। पीएम ने स्पष्ट किया कि दुनिया के कई देशों में जहां एआई को लेकर भय का माहौल है, वहीं भारत इसे अपने 'भाग्य' और उज्ज्वल भविष्य के रूप में देख रहा है। भारत इसे अपनी विकास यात्रा का अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता है। मोदी ने एआई के लिए एक नया ग्लोबल फ्रेमवर्क दिया। उन्होंने कहा कि एआई नैतिक, जवाबदेह, संप्रभुता,सुलभ और वैध होना चाहिए, ताकि यह केवल डेटा पॉइंट न बनकर मानवता के कल्याण का जरिया बने।

● **कंटेंट पर ऑथेंटिसिटी लेबल की जरूरत-** पीएम ने सुझाव दिया कि जैसे खाने के सामान पर न्यूट्रिशन लेबल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी स्पष्ट लेबल होना चाहिए। इससे लोगों को पता चल सकेगा कि क्या असली है और क्या एआई द्वारा बनाया गया (फैब्रिकेटेड) है। भारत ने दुनिया की कॉन्फिडेंशियल सोच से अलग हटकर एआई कोड को ओपन शेयर करने की बात कही। पीएम का मानना है कि जब तकनीक सबके लिए खुली होगी, तभी दुनिया भर के युवा दिमाग उसे बेहतर और सुरक्षित बना पाएंगे। पीएम ने कहा कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा।

अंबानी बोले-

● **साबित करेंगे कि एआई नौकरियां नहीं छीनता-** रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई नौकरियां छीनने के बजाय हाई-स्किल काम के नए मौके पैदा करेगा। उन्होंने एआई की तुलना महाभारत के 'अक्षय पात्र' से की। अंबानी ने एलान किया कि रिलायंस अगले 7 सालों में ?10 लाख करोड़ का निवेश करेगी। अंबानी ने ये भी बताया कि जामनगर में मल्टी-गीगावाट एआई डेटा सेंटर का काम शुरू हो गया है। साल 2026 के दूसरे हिस्से तक 120 वाट से ज्यादा की क्षमता शुरू हो जाएगी।

सुंदर पिचाई बोले-

● **अरबों लोगों की जिंदगी बदलेगा एआई-** गूगल भारत में अपने 15 बिलियन डॉलर (1.35 लाख करोड़ रुपए) के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के हिस्से के रूप में एक फुल स्टैक एआई हब स्थापित कर रहा है। इस हब में गीगावाट स्केल की कंप्यूटिंग और एक नया इंटरनेशनल सब-सी केबल गेटवे होगा। हर किसी के लिए उपयोगी एआई बनाने के लिए हमें साहसिक कदम उठाने होंगे, क्योंकि यह अरबों लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है और सबसे कठिन समस्याओं को हल कर सकता है। हमें उन क्षेत्रों को देखना होगा।

देश का पहला नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर बनाएगा टाटा ग्रुप

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा ग्रुप अगली पीढ़ी की एआई ट्रेनिंग और इंफ्रेंस के लिए खास तौर पर तैयार भारत का पहला लार्ज-स्केल एआई-ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर बना रहा है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने इसकी पहली 100 मेगावाट क्षमता बनाने के लिए ओपन एआई के साथ साझेदारी की है, जिसे आगे चलकर एक गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 20 फरवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

जेल में बंद बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को जमानत

सुप्रीम कोर्ट का सुझाव- समझौते से सुलझाएं मामला; 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

उदयपुर (एजेंसी)। फिल्म बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोनों को नियमित जमानत (रेगुलर बेल) दे दी। इससे पहले 13 फरवरी को श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत दी गई थी। वह जेल से बाहर आ चुकी हैं। विक्रम भट्ट को 7 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुझाव भी दिया है। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को मिडिएशन सेल (मध्यस्थता केंद्र) में जाने को कहा है।

कोर्ट का मानना है कि दोनों पक्षों को वहां उपस्थित होकर आपसी समझौते से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। विक्रम भट्ट के वकील कमलेश दवे ने कोर्ट में अपनी दलील पेश की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह एक तरह का कमर्शियल डिस्प्यूट (व्यापारिक विवाद) है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस मामले को मुंबई कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए बेवजह मजबूर न किया जाए।

वर्षा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के हित में तत्पर है राज्य सरकार : कृषि मंत्री कंषाना

भोपाल (नप्र)। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और हर परिस्थिति में किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। हाल ही में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई वर्षा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के नुकसान की राहत राशि देने के लिए गंभीरता से कार्य किया जाएगा।

कृषि मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि जिन-जिन जिलों में वर्षा और ओलावृष्टि की घटनाएं सामने आई हैं, वहां तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सर्वे कार्य पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि प्रभावित किसानों को राहत राशि का भुगतान समय पर किया जा सके। मंत्री श्री कंषाना ने आश्वासन दिया कि किसी भी किसान को नुकसान की स्थिति में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

कृषि मंत्री श्री कंषाना ने किसानों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें तथा स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करें। सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को शीघ्र राहत प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है और भविष्य में भी किसान कल्याण के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी।

मां के पाले-पोसे बच्चे के लिए पिता का सरनेम जरूरी नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, बच्चे के अधिकार सुरक्षित

नई दिल्ली (एजेंसी)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि अगर बच्चे का पालन पोषण अकेले मां करती है तो उसे पिता की जाति और सरनेम रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने एक लड़की को स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम और जाति बदलने की इजाजत देते हुए कहा है कि जिस बच्चे को सिर्फ उसकी मां ने पाला है, उसे सिर्फ इसलिए अपने पिता का नाम, सरनेम और जाति रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि एक फार्मेट में पहले इसकी जरूरत थी। कोर्ट ने कहा कि जो समाज डेवलप होने का दावा करता है, वह इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि बच्चे की पब्लिक पहचान उसके पिता से जुड़ी हो जो बच्चे की जिंदगी से दूर हो, जबकि मां, जो बच्चे के पालन-पोषण का पूरा बोझ उठाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सेकेंडरी बनी रहे। यह आदेश एक 12 साल की लड़की की याचिका पर आया है। बच्ची ने स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम ठीक करने और जाति की एंट्री को 'मराठा' से 'शेड्यूल्ड कास्ट- महार' में ठीक करने की मांग की थी।

राज्यसभा चुनाव में खेल बिगाड़ने के मूड में ओवैसी

● बिहार में एआईएमआईएम ने कर दिया उम्मीदवार उतारने का ऐलान

पटना (एजेंसी)। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। लेकिन इसी बीच चुनाव को लेकर दोनों गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन का गणित उलझ गया है। बिहार में सीमांचल में दो विधानसभा चुनाव में लगातार अपनी ताकत दिखा चुकी एआईएमआईएम ने 5वीं सीट में पेच फंसा दिया है। बिहार एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने गुरुवार को साफ कहा कि उनकी पार्टी किसी को समर्थन देने के बजाय खुद अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। दरअसल, इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम बड़ी भूमिका में नजर आने वाली है। बिहार में एआईएमआईएम के पांच विधायक हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यसभा चुनाव पर बात की। अख्तरुल ईमान ने कहा कि जो लोग इस फिरकापरस्त सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते

हैं, जो लोग दलितों के हित की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के बाजुओं को मजबूत करना चाहिए। राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने के प्रश्न पर एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान भड़क गए। उन्होंने कहा, क्या मेरा जन्म समर्थन देने के लिए ही हुआ है। आप लोग यह क्यों नहीं बोलते कि मुझे समर्थन कौन देगा। इन लोगों के राज्यसभा में प्रतिनिधि हैं, राज्यसभा में हमारा कोई नहीं है। राज्यसभा में कई दलों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन एआईएमआईएम का कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में पार्टी अब अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। अभी एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं। इसके आधार पर, एनडीए आसानी से चार सीटें जीत सकता है। चार सीटें जीतने के बाद भी उसके पास कुछ वोट बचे हैं, लेकिन अगर मुकाबला होता है, तो पांचवीं सीट जीतने के लिए उसे अन्य विधायकों की जरूरत पड़ेगी।

शहडोल में लकड़ी माफियाओं ने वन विभाग की टीम को बंधक बनाकर पीटा, रेंजर समेत कई घायल

शहडोल (नप्र)। जिले में वन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं। वे जंगलों की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। ताजा मामला उत्तर वन मंडल के वन परिक्षेत्र के सीधी सर्किल अंतर्गत महादेवा क्षेत्र से सामने आया है, जहां बेशकीमती सरई लकड़ी की अवैध कटाई और तस्करी को रोकने पहुंचे वन विभाग के अमले पर लकड़ी माफियाओं ने हमला कर दिया। जिससे वन कर्मी घायल हो गए हैं।

शहडोल के उत्तरवन मंडल के अमझोर वन परिक्षेत्र के रेंजर तरुणेंद्र सिंह को महादेवा क्षेत्र में सरई लकड़ी की मशीन से अवैध कटाई एवं परिवहन की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके पर महेंद्र यादव और सुरेन्द्र यादव को लकड़ी की कटाई और तस्करी करते हुए पकड़ा लिया। आरोपियों ने पहले वन अमले को कार्रवाई न करने के लिए दबाव बनाया और फिर अवैध कटाई के दूसरे स्थान पर ले जाने का बहाना बनाकर टीम को महादेवा के अंदरूनी क्षेत्र में ले गए। जहां पहले से मौजूद अन्य लोगों के साथ मिलकर माफियाओं ने वन कर्मियों को बंधक बना लिया। साथ ही लाठी-डंडों और पत्थरों से बेरहमी से हमला कर दिया।

इस हमले में रेंजर तरुणेंद्र सिंह और डिप्टी रेंजर दुर्गा प्रसाद अहिरवार सहित कई बीट गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, कुछ कर्मचारियों के सिर फूट गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं।

बंधक बनाकर किया हमला

इस पूरे मामले में डीएफओ उत्तर वन मंडल तरुणा वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरई की लकड़ी की कटाई कर तस्करी की सूचना पर वन अमला कार्यवाही करने पहुंचा था। तभी कुछ लोगों ने उन्हें बंधक बनाकर उनके ऊपर हमला कर दिया। जिससे रेंजर, डिप्टी रेंजर सहित बीट गार्ड घायल हुए हैं। मामले की शिकायत जयसिंहनगर थाने में की गई है। वहीं, इस मामले में जयसिंहनगर थाना प्रभारी अजय बैगा का कहना है कि वन कर्मियों पर हमले की शिकायत आई है, जिस पर मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में शहडोल मुख्यालय से लगे दक्षिणी वन मंडल क्षेत्र में भी कोल माफियाओं द्वारा गश्त कर रही फॉरेस्ट टीम पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें रेंजर सहित कई वनकर्मी घायल हुए थे। लगातार हो रहे इन हमलों ने जंगलों की सुरक्षा में लगे अमले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पंजाब सीएम ऑफिस-चंडीगढ़ कोर्ट उड़ाने की धमकी

● पुलिस-बीएसएफ ने सेक्रेटेरिएट में सर्च ऑपरेशन चलाया

चंडीगढ़ (एजेंसी)। चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय और चंडीगढ़ कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। एहतियातन हरियाणा सचिवालय को भी अलर्ट पर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक, धमकी भरा ईमेल संबंधित विभाग को मिला था, जिसमें सीएम ऑफिस में विस्फोट करने की बात कही गई है। इस ईमेल का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। हालांकि, इसकी पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और लोगों को सचिवालय से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। पुलिस बल, बीएसएफ, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड की टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी ली।

चुनाव से पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टी को झटका

● तमिलनाडु में खेला, पाला बदल कर दिया डीएमके का साथ

नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु की सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (डीएमडीके) के साथ गठबंधन कर लिया है। गठबंधन का यह फैसला विपक्षी खेमे में सेंध लगाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। डीएमडीके प्रमुख प्रेमलता विजयकांत ने गुरुवार सुबह चेन्नई स्थित मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के तुरंत बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गठबंधन की आधिकारिक जानकारी दी। उन्होंने स्टालिन के साथ ली गई फोटो शेयर करते हुए

लिखा, आइए हम गवर्नेंस के द्रविड़ मॉडल को जारी रखने और तमिलनाडु को हर तरह से प्रोग्रेस करने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ें। प्रेमलता ने आगे कहा, हमें यकीन है कि हमारा अलायंस 200 से ज्यादा सीटें जीतेगा। उन्होंने साफ किया कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला बाद में घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने डीएमडीके का स्वागत किया। उन्होंने पार्टी के संस्थापक कैप्टन विजयकांत को श्रद्धांजलि भी दी। प्रेमलता विजयकांत ने अपने दिवंगत पति का जिक्र करते हुए कहा,हमारे कैडर भी यही चाहते थे। यह तब बन जाना चाहिए था जब कैप्टन विजयकांत जिंदा थे। यह गठबंधन डीएमके के लिए बड़ी रणनीतिक जीत साबित हो सकता है क्योंकि डीएमडीके पिछले 15 साल से एआईएडीएमके के साथ जुड़ी हुई थी। मध्य तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, पुदुक्कोट्टई, विरुधाचलम, ऋषिवंदियम, कल्लाकुरिची और उलुंदुरपेट जैसे इलाकों में डीएमडीके का मजबूत जनाधार है। 2011 में पार्टी ने 29 सीटें और 7.9 प्रतिशत वोट हासिल किए।

डैमेज कंट्रोल में जुटे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

● खुद के आवास पर 101 बटुकों का किया सम्मान

लखनऊ (एजेंसी)। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के प्रयास में लगी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रयास को धीमा करने पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर गंभीर हुई बसपा और सपा के कदम को थामने के लिए पाठक ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर सौ बटुकों का सम्मान किया। उत्तर प्रदेश में प्रतीकों की राजनीति का रंग गाढ़ा होता जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की शिखा खींचने वाले पुलिसकर्मियों को 'पापी' कहा, वहीं गुरुवार को अपने राजभवन कालोनी स्थित आवास पर 101 बटुकों का पूजन कर ब्राह्मण राजनीति का पताका अपने हाथ में रखने का संदेश दिया है। उनका यह संदेश इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।

हाल में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में बिना नाम लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला बोलते हुए कहा था 'कोई स्वयं को कैसे शंकराचार्य कह सकता है।

स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस

● चुनाव के दौरान नॉमिनेशन में गलत जानकारी देने का है आरोप

पटना (एजेंसी)। पटना हाईकोर्ट ने पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इन 42 विधायकों में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक चेतन आनंद और गोह से राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद के नाम शामिल हैं। इन विधायकों पर चुनाव के दौरान वोट चोरी करने और नॉमिनेशन के दौरान चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने जीते हुए विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी देने और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों को लेकर उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित विधायकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया।

हिमाचल में टूरिस्ट वाहनों की एंट्री-फीस ढाई गुना तक बढ़ी

कार, जीप पर 70 की जगह 170 रुपये लगेंगे, 1 अप्रैल से नई दरें लागू

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश की सैर महंगी होने वाली है। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की एंट्री फीस 30 रुपए से लेकर 230 रुपए प्रति वाहन बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने नई दरें अधिसूचित कर दी है, जो कि एक अप्रैल 2026 से लागू होनी है। हिमाचल प्रदेश टोल्स एक्ट, 1975 के तहत अधिसूचित की गई नई दरों का असर न केवल बाहरी राज्यों के टूरिस्ट पर पड़ेगा, बल्कि सामान की ढुलाई की दरों में भी इजाफा होगा। सरकार ने प्राइवेट कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों पर लगने वाली एंट्री फीस 70 रुपए से बढ़ाकर सीधे 170 रुपए कर दी है। यानी 100 रुपए का इजाफा किया गया। इसी तरह, 12 प्लस 1 सीटर पैसेंजर वाहनों का शुल्क 110 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए किया गया है। मिनी बस (32 सीटर) का शुल्क 180 रुपए से बढ़ाकर 320 रुपए, जबकि कमर्शियल बसों के लिए शुल्क 320 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली मशीनरी पर लगने वाला शुल्क 570 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए, बड़े मालवाहक वाहनों का शुल्क 720 रुपए से बढ़ाकर 900 रुपए, ट्रैक्टर के प्रवेश शुल्क में भी बढ़ोतरी करते हुए इसे 70 रुपए से 100 रुपए कर दिया गया है, जबकि डबल एक्सल बस-ट्रक की 570 रुपए (कोई बदलाव नहीं) फीस रखी गई है। एंट्री फीस की वसूली बैरियरों पर ही की जाएगी।

तकनीकी शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने क्रिस्प भोपाल में बीपीसीएल के सीएसआर अंतर्गत प्रशिक्षण शिविर परियोजना 'स्वावलंबन' के समापन समारोह में, प्रशिक्षित युवाओं को प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति पत्र वितरित किए।

डॉ. सिन्हा की पुस्तक का लोकार्पण आज

भोपाल। डॉ. वीणा सिन्हा की चयनित कविताओं की पुस्तक का लोकार्पण 20 फरवरी को शाम 6 बजे दुष्यंत कुमार पांडुलिपि स्मारक संग्रहालय, शिवाजी नगर में रखा गया है। रचना समय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका के विमोचन के संग काव्य पाठ एवं डॉ. सिन्हा की कविताओं पर आधारित लघुनाटक का मंचन भी होगा। काव्य पाठ वरिष्ठ कवि निरंजन श्रोत्रिय, राग तेलंग और अपर्णा पात्रीकर करेंगे।

स्वर रंग आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा डॉ. वीणा सिन्हा की कविताओं पर आधारित लघु नाटक %तुम फिर भी जीना लड़की% के मंचन में सजीव संगीत ख्यात सितार वादिका स्मिता नागदेव एवं निर्देशन राहुल शर्मा %राहुल्य% का है।

विक्रमोत्सव 2026: समाज परिवर्तन पर मंथन करता नाटक 'भरतवाक्य' मंचित

उज्जैन डॉ. जफर महमूद

उज्जैन में आयोजित विक्रमोत्सव के विक्रम नाट्य समारोह की तीसरी संध्या नाटक 'भरतवाक्य' का सफलतापूर्वक मंचन हुआ। कालिदास अकादमी के संकुल भवन में उड़ीसा के अनुभवी निर्देशक हाराप्रसाद पट्टनायक के निर्देशन में नवाचारों से युक्त नाट्य प्रदर्शन ने दर्शकों की प्रशंसा अर्जित की। भरतवाक्य संस्कृत नाटकों के अंत में आने वाला वह पद श्लोक होता है जिसमें नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए नाटककार लोक कल्याण की कामना करते हैं। यह नाटक के समापन पर पात्रों द्वारा जनसाधारण के लिए दिए जाने वाला संदेश होता है। मंचित नाटक में यह संदेश दिया गया था कि नाटक के जरिए समाज में सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए। यह नैतिक जिम्मेदारी कलाकार और समाज दोनों की है।

महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ, संस्कृति विभाग मध्यप्रदेश शासन तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विक्रम नाट्य समारोह में मंचित नाटक में रंगकर्म की आत्मालोचना प्रस्तुत की गई। नाटक की कथा रंगकर्म और कलाकार पर केंद्रित रही, जिसका उद्देश्य समाज, नैतिक मूल्यों और कलाकार की सामाजिक जिम्मेदारी पर चिंतन कराना है। प्रस्तुति में यह प्रश्न भी उठाया गया कि मंच से बोले गए आदर्श वाक्य वास्तव में समाज में बदलाव ला सकते हैं। परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। नाटक पूरी तरह व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुति के आरंभ में उज्जैन प्रेस क्लब के अध्यक्ष नंद लाल यादव एवं विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. बालकृष्ण शर्मा ने नाट्य निर्देशक हाराप्रसाद पट्टनायक का सरस्वत सम्मान किया।

शिवाजी जयंती पर भव्य शोभायात्रा

अतिथियों ने अर्पित की श्रद्धांजलि, पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

भोपाल (नप्र)। भोपाल में महाराष्ट्रीयन कुणबी पाटिल सेवा समिति द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर भव्य शोभायात्रा और चल समारोह का आयोजन श्रद्धा, उत्साह और सांस्कृतिक गरिमा के साथ किया गया। वहीं मंत्री सारंग में रैली में शामिल हुए। लिंक रोड नंबर-1 स्थित नानके पेट्रोल पंप से शुरू हुई रैली में

समाज के महिला-पुरुष और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जय भवानी-जय शिवाजी के जयघोष से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वरूप धारण किए कलाकार को नमन कर माल्यार्पण किया। उन्होंने अपने संबोधन में शिवाजी महाराज के शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रनिष्ठा को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

इस अवसर पर भोपाल की महापौर मालती राय ने भी शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए समाज की एकता और सांस्कृतिक परंपराओं की सराहना की।

बालिकाओं ने दी लोकनृत्य की प्रस्तुति

प्रतिमा स्थल पर पहुंचने के बाद पारंपरिक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। महिलाओं और बालिकाओं के लोकनृत्य ने उपस्थित लोगों को भावविभोर कर दिया।

समिति के अध्यक्ष के. बी. पाटिल के नेतृत्व में आयोजन व्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समिति ने कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी समाजजनों, अतिथियों और सहयोगकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रेमी संग भागी पत्नी, पति ने किया सुसाइड

2 मिनट 57 सेकंड का वीडियो बनाकर दोनों को बताया मौत के लिए जिम्मेदार

भोपाल (नप्र)। भोपाल के निशातपुरा में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने मौत के लिए पत्नी और उसके प्रेमी को जिम्मेदार बताया है। घटना बुधवार रात 10 बजे की है, जबकि पोस्टमॉर्टम के बाद गुरुवार दोपहर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, 30 वर्षीय पंकज अहिरवार पिता कुंजीलाल अहिरवार रतन कॉलोनी में रहता था। वह एक प्राइवेट कंपनी में गैस सिलेंडर डिलेवरी का काम करता था। बुधवार रात पंकज ने घर में फांसी लगा ली। सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने सुसाइड के लिए मजबूर करने के

आरोप अपनी पत्नी संध्या और उसके प्रेमी विकास पालकर पर लगाए हैं। युवक ने अपने आखिरी वीडियो में विकास और पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

पत्नी ने की थी पुलिस से शिकायत, इससे डिप्रेशन में आया था

युवक ने वीडियो में इस बात का भी जिक्र किया कि पत्नी ने गांधी नगर थाने में उसके खिलाफ शिकायत की थी, जिससे लंबे समय तक वह परेशान रहा, उसे कई बार थाने में रखा गया। इन तमाम चीजों से परेशान होकर वह अपनी जान दे रहा है।

पंकज ने आखिरी वीडियो में बताया कि पत्नी को उसका प्रेमी विकास अपने साथ खुरई ले गया है। कई बार बुलाने पर भी पत्नी लौटने को तैयार नहीं है। उलटा उस पर अनर्गल आरोप लगाकर जेल में बंद करने की धमकी देती है।

भाई बोला- विकास से घंटों बात करती थीं भाभी- मृतक के छोटे भाई गगन ने बताया कि भाभी संध्या विकास से फोन पर घंटे तक बातें करती थीं। इस बात से नाराज होकर भैया उनको फटकार लगाते थे। दोनों के बीच इसी बात को लेकर कई बार विवाद होते थे। पिछले दिनों भाभी, भैया को छोड़कर विकास के साथ रहने चली गईं। इससे डिप्रेशन में आकर भैया ने सुसाइड कर लिया। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी आखिरी वीडियो में भी किया है। तमाम सबूत पुलिस को सौंप दिए हैं, लेकिन पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है।

पीपुल्स यूनिवर्सिटी

मिली बम से उड़ाने की धमकी

ईमेल से साइनाइड गैस वाले ब्लास्ट की चेतावनी, 12:15 बजे विस्फोट का दावा, खाली कराया परिसर

भोपाल (नप्र)। राजधानी स्थित पीपुल्स यूनिवर्सिटी को गुरुवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी के डीन को ईमेल भेजकर दावा किया गया कि कॉलेज भवन में साइनाइड (जहर) वाले बम रखे गए हैं, जो दोपहर 12:15 बजे फटेंगे। मेल में सुबह 11 बजे तक डॉक्टरों और छात्रों को परिसर से बाहर निकालने की चेतावनी दी गई थी। सूचना मिलते ही प्रशासन ने एहतियातन यूनिवर्सिटी खाली कराई और पुलिस व बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया।

- **डीन को आया धमकी भरा ईमेल-** जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के डीन को आधिकारिक मेल आईडी पर एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ। इसमें लिखा था कि कॉलेज परिसर में साइनाइड वाले बम लगाए गए हैं, जो तय समय पर विस्फोट करेंगे। मेल में धार्मिक नारे का भी उल्लेख किया गया था। संदेश में स्पष्ट रूप से सुबह 11 बजे तक डॉक्टरों और विद्यार्थियों को बाहर निकालने को कहा गया था।
- **तुरंत खाली कराया गया परिसर-** ईमेल मिलते ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। सुरक्षा के मद्देनजर परिसर को तत्काल खाली कराया गया। क्लासरूम, ओपीडी और प्रशासनिक भवनों से छात्रों व स्टाफ को बाहर निकाला गया। मौके पर बम

निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड ने पहुंचकर जांच शुरू की। संदिग्ध स्थानों की गहन तलाशी ली गई।

- **पुलिस जांच में जुटी-** पुलिस अधिकारियों के अनुसार ईमेल की तकनीकी जांच की जा रही है।

एहतियातन परिसर को खाली कराया

पीपुल्स विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अधिकाधिक बयान जारी कर कहा कि पीपुल्स मेडिकल कॉलेज परिसर को दोपहर 12:15 बजे बम से उड़ाने की सूचना ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई थी। हमने एहतियातन पूरे परिसर को तत्काल खाली कर नजदीकी पुलिस थाने को भी सूचित किया। मौके पर पुलिस एवं बम स्क्वॉड की टीम पहुंचकर सघन जांच में जुटी रही। प्रारंभिक जांच के दौरान मौके पर कोई संदिग्ध वस्तु या आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त नहीं हुई। प्रशासन द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

मेल में लिखा हुआ है यह संदेश

टीएनएलए एस. मारन विंग से रमीजा हुसैन ने लिखा- तमिलनाडु के कांस्टेबलों को निवेथा पेथुराज उदयनिधि और अन्य डीएमके (आपत्तिजनक शब्द) के कपड़े और गंदे बर्तन साफ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस कारण कई लोगों ने अपमान का अनुभव किया है। इसलिए, मनीस्ट और पाक 151 सेल के पूर्व क्यू ब्रांच सदस्य, जो मदुरै में संचालित हैं, ने आज आपके मेडिकल कॉलेज को ट्विनिंग आईईडी लगाकर निशाना बनाया है। जहां साइनाइड गैस से युक्त दोनों आईईडी एक साथ विस्फोट करेंगे, ताकि इस प्रथा के खिलाफ बयान दिया जा सके और तमिलनाडु में कांस्टेबलों के लिए 1979 के नैनार दास पुलिस यूनियन की सिफारिशों को लागू किया जा सके। हमारी मांगों को सुनाने का हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, क्षमा करें। यदि किसी कारणवश वे सक्रिय नहीं होते हैं, तो सदस्य स्वयं मेडिकल कॉलेज के अंदर आएंगे और श्रीलंकाई ईस्टर आत्मघाती अभियान की तरह सभी स्टाफ के साथ खुद को उड़ा लेंगे। हम बयान देना चाहते हैं और आपका कार्यालय वर्तमान में सबसे आसान लक्ष्य है। हम जिम्मेदारी लेते हैं और चाहते हैं कि हमारी आवाज किसी भी कीमत पर सुनी जाए।

यदि आकाश भास्करन पकड़ा जाता है, तो निवेथा पेथुराज भी पकड़ी जाएंगी। इसलिए, कृपया उससे पहले परिसर खाली कर दें। डेविडसन देवासीवथम आईपीएस ने 2022 में अपनी पत्नी की ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से पूर्व एलटीटीई कैडरों को फर्जी पासपोर्ट जारी किए।

गर्म तेल से भरी कढ़ाई में गिरा हलवाई

- **पूरियां तलते समय आया था चक्कर, बुरी तरह झुलसा, मौत**

भोपाल (नप्र)। भोपाल के परवलिया इलाके में एक समारोह में खाना बनाते समय हलवाई गर्म तेल से भरी कढ़ाई में जा गिरा। साथियों ने करीब दो मिनट की मशक्कत के बाद उसे कढ़ाई से बाहर निकाला। तत्काल उसे हमीदिया अस्पताल पहुंचाया। जहां 15 दिन चले इलाज के बाद गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई। हादसे के समय युवक पूरियां तल रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सज्जाद अली पति हसन अली 34 साल निवासी गोंडीपुरा नई जेल हलवाई था। 4 फरवरी को मुबारकपुर में एक गार्डन में खाना बनाते समय चक्कर आ गए। इस दौरान वह तेल से भरी कढ़ाई में गिर गया। इस कढ़ाई में पूरियां तली जा रही थीं, जिससे युवक गंभीर रूप से झुलस गया। साथियों ने उसे किसी तरह से बाहर निकाला।

बॉडी परिजनों को सौंप दी

इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया। जहां गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। गुरुवार दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को परिजनों के हवाले कर दिया गया है।

परिवार वाले तलाश रहे थे लड़की- सज्जाद की शादी नहीं हुई थी। उसके परिवार वाले लड़की तलाश रहे थे। वह चार भाईयों में दूसरे नंबर का था। शादी पार्टियों में खाना बनाने का आर्डर लेता था। हमेशा परिवार वालों को भोपाल का बड़ा केटरर बन कर दिखाने की बात कहता था।

भोपाल में पहली बार फेमिना मिस इंडिया एमपी ग्रैंड फिनाले

16 फाइनलिस्ट में ताज की जंग, सस्टेनेबिलिटी थीम बनेगी 60 साल की विरासत की पहचान

भोपाल (नप्र)। देश को फेमिना मिस इंडिया जैसे बड़े मंच ने सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय बच्चन और प्रियंका चोपड़ा जैसी विश्वस्तरीय हस्तियां दी हैं। अब पहली बार इसका स्टेट ग्रैंड फिनाले मध्यप्रदेश के भोपाल में होने जा रहा है। वर्ष 2026 में मप्र में आयोजित होने वाला यह आयोजन सिर्फ सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं, बल्कि 'सस्टेनेबिलिटी-फर्स्ट, जीरो-वेस्ट इवेंट' की थीम पर आधारित एक सामाजिक संदेश भी होगा। भोपाल में होने वाले इस भव्य आयोजन में पूरे प्रदेश से चुनी गई 16 प्रतिभागी ताज के लिए मुकाबला करेंगी और विजेता राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी।

- **पहली बार मध्यप्रदेश में स्टेट ग्रैंड फिनाले-** फेमिना मिस इंडिया की 60 वर्षों से अधिक पुरानी विरासत रही है। इस मंच ने भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली कई हस्तियां दी हैं। वर्ष 2026 में पहली बार इसका स्टेट ग्रैंड फिनाले मध्यप्रदेश में आयोजित किया जा रहा है।

150 प्रतिभागियों में से 16 फाइनलिस्ट

इस प्रतियोगिता में पूरे मध्यप्रदेश से लगभग 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विभिन्न राउंड और स्क्रीनिंग के बाद ग्रैंड फिनाले के लिए 16 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। ग्रैंड फिनाले में विजेता को स्टेट लेवल क्राउन दिया जाएगा। इसके बाद करीब डेढ़ महीने बाद वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अन्य राज्यों की विजेताओं के साथ मुकाबला करेंगी और मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी।

ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर में संध्या और शयन आरती की बुकिंग पूरी तरह हुई ऑनलाइन

संध्या आरती की बुकिंग दोपहर 12 बजे से और शयन आरती की बुकिंग शाम 4 बजे से

भोपाल (नप्र)। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन व्यवस्था को और अधिक सुगम, पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए मंदिर प्रबंध समिति ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उज्जैन में डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया का विस्तार करते हुए, समिति ने बाबा महाकाल की 'संध्या आरती' और 'शयन आरती' की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। अब देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु घर बैठे ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आरती में शामिल होने के लिये अपना स्थान सुनिश्चित कर सकेंगे। श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर मंदिर की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ही बुकिंग कर सकते हैं।

संध्या आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से शुरू होगी और शयन आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रतिदिन शाम 4:00 बजे से की जा सकेगी। दोनों ही आरतियों के लिए प्रति श्रद्धालु 250 रूपये का शुल्क (शीघ्र दर्शन के समान) निर्धारित किया गया है। बुकिंग की यह प्रक्रिया पूर्णतः 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर संचालित होगी।

बाबा महाकल की आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश द्वार क्रमांक 1 से ही प्रवेश दिया जाएगा। संध्या आरती के लिए शाम 6:00 बजे तक प्रवेश करना अनिवार्य होगा। शयन आरती के लिए रात 10:00 बजे तक ही प्रवेश मिल सकेगा।

आरती के दौरान जारी रहेंगे चलित दर्शन

मंदिर प्रबंधन ने यह स्पष्ट किया है कि दोनों आरतियों के निर्धारित समय के दौरान 'चलित दर्शन' की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी। इससे वे श्रद्धालु जो आरती की बुकिंग नहीं कर पाए हैं, वे भी कतार में चलते हुए सुगमता से बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार, इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी और श्रद्धालु-अनुकूल बनाना है, ताकि उज्जैन पहुँचने वाले हर भक्त को एक सुखद और दिव्य अनुभव प्राप्त हो सके।

4 साल में 2947 मामलों में लोकायुक्त का एक्शन

1379 भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ जांच, 134 मामलों में चालान की मंजूरी नहीं

भोपाल (नप्र)। लोकायुक्त में बीते चार वर्षों में मध्यप्रदेश के 1379 अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध जांचें चल रही हैं। जांच के दायरे में आए मामलों में 20.97 करोड़ रुपए की वसूली किए जाने के बावजूद 134 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति में लंबित हैं। वहीं 39 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई की गई है और 208 प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किए जा चुके हैं। यह जानकारी कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दी। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त संगठन में वर्ष 2022-23 से अब तक 1884 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जबकि विशेष पुलिस स्थापना में 1063 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। इन मामलों में शिकायत एवं जांच शाखा तथा तकनीकी शाखा द्वारा इसी अवधि में 1592 जांच पूरी कर प्रकरणों का निराकरण किया है। वर्तमान में शिकायत एवं जांच शाखा में 1291 तथा तकनीकी शाखा में 88, कुल 1379 प्रकरण जांच के दायरे में हैं।

134 केस अभियोजन स्वीकृति में लंबित- लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा पंजीबद्ध 1063 आपराधिक प्रकरणों में से 393

प्रकरणों की विवेचना पूरी की जा चुकी है। इनमें 134 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति में लंबित हैं। वहीं 39 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई की गई है और 208 प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किए हैं। इसके अतिरिक्त 12 प्रकरणों में न्यायालय में खात्मा पेश किया है, जिनमें आरोपी की मृत्यु अथवा प्रकरण के उन्मोचित होने का आधार रहा। शेष 670 प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन हैं।

153 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई

जवाब में यह भी बताया गया कि कुल जांच किए गए मामलों में शिकायत एवं जांच शाखा के 146 तथा तकनीकी शाखा के 7, कुल 153 प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही शिकायत एवं जांच के आधार पर 20 करोड़ 97 लाख 17 हजार 905 रुपए की वसूली की गई है। लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा न्यायालय में पेश किए गए 208 चालानों में से 7 प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध दोष सिद्ध हुआ है। इन मामलों में संबंधित आरोपियों के खिलाफ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-6-2/98/3/1 दिनांक 26 मई 1998 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

कांग्रेस विधायक ने पूछा था यह सवाल- कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने विधानसभा के माध्यम से राज्य सरकार से पूछा था कि वर्ष 2022-23 से वर्तमान तक लोकायुक्त संगठन में कुल कितने प्रकरण प्राप्त हुए, कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया और कितने वर्तमान में लंबित हैं। साथ ही कितने प्रकरणों में दोष सिद्ध हुआ, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई प्रस्तावित की गई तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए शासन द्वारा क्या कार्ययोजना और समय-सीमा निर्धारित की गई है।

खरगोन में गिरोह ने तीन जिलों से चुराई 13 बाइक

बाल अपचारी सहित चार गिरफ्तार, निशाने पर थे मेला-बाजार

खरगोन (नप्र)। खरगोन पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 6.50 लाख रुपये कीमत की चोरी की 13 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। यह गिरोह मेला, हॉट बाजार और सार्वजनिक स्थानों से बाइक चुराता था।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) रवींद्र वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब एक बिना नंबर की सीडी डीलक्स बाइक को रोककर उसके सवार आनंदबेड़ी निवासी आमिन उर्फ कालू पिता भूरू खान और हातिम पिता कल्लू खान से दस्तावेज मांगे गए। वे बाइक के कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए।

संपादकीय

विवादों में एआई समिट

देश की राजधानी दिल्ली में हो रही भव्य एआई इम्पैक्ट समिट का अपनी सकारात्मक पहलों से ज्यादा विवादों में रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह समिट पहले दिन से अपनी रचनात्मक गतिविधियों से ज्यादा अव्यवस्था और अफरा-तफरी के कारण ज्यादा चर्चित रही है। हालात की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लोगों को हो रही सुविधा के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। यह एआई समिट अपने आप में विशाल मेले की तरह है, जिसमें करीब ढाई लाख लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं। यह मोदी सरकार द्वारा दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश है कि भारत आईटी के क्षेत्र में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है और इस मामले में दक्षिण एशिया में लीडर की भूमिका निभाना चाहता है। लेकिन इस एआई समिट में जो नजारे दिख रहे हैं, वह भारत की इस महत्वाकांक्षा को मजबूती देते नहीं दिखते। क्योंकि समिट के कुप्रबंधन के साथ साथ एक निजी गलगोटिया विश्वविद्यालय द्वारा एआई के क्षेत्र में अपनी फर्जी उपलब्धियां दिखाने की हरकत के चलते भारत का सिर नीचा ही हुआ है। हालांकि अब इस विवि को समिट से बाहर कर दिया गया है, लेकिन जो नुकसान होना था, वो तो हो ही चुका है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा कि उन्होंने चीन निर्मित एक रोबो डॉग को अपना बताकर समिट में पेश किया। इसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा रही जिसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर माफी भी मांगी। यूनिवर्सिटी ने कहा कि यह गलतफहमी की वजह से हुआ था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी शैक्षणिक ईमानदारी, पारदर्शिता और अपने काम की ज़िम्मेदार प्रस्तुति को लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन लोगों ने इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा की जा रही लीपा-पोती ही माना। उलटे वहां की एक प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा कि रोबोट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ़ एक्सिलेंस में डेवलप किया जा रहा है, न कि इसे बनाया गया है, बिल्ड करना और डिवेलप करने में अंतर है। उन्होंने यह दावा भी किया कि गलगोटिया के कैंपस में भारत का पहला ड्रोन सॉकर एरीना (किसी ख़ास गतिविधि की जगह) है, इस एरीना में स्टूडेंट्स गेम्स खेलते हैं, इसको फ़्लाई करते हैं और नए तरीक़े से एनहांस्ड फ़ीचर के साथ इसे डिवेलप कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के इन दावों का दुनिया भर में मजाक उड़ा। पता चला कि विवि ने दूसरे देशों के मॉडल को ही अपना बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। सवाल यह भी है कि खुलेआम एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर धांधली करने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है, उसे इस प्रतिष्ठित समिट में एंट्री कैसे मिली? बताया जाता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की शुरुआत साल 2011 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुई थी। इसके संस्थापक गलगोटिया पब्लिकेशंस के मालिक सुनील गलगोटिया हैं। इस पब्लिकेशन हाउस ने कामयाबी की उड़ान भरी जब उसे विदेश में पढ़ाई के लिए दी जाने वाली परीक्षा सैट, टॉफ़ेल, जीआरई और जीमैट के लिए बैरंस किताबों का प्रकाशन अधिकार मिला। इसके बाद सुनील गलगोटिया ने किताब से निकलकर शिक्षा के क्षेत्र में हाथ फैलाने का फ़ैसला किया। तक़रीबन 200 कोर्स चलाने का दावा करने वाली इस यूनिवर्सिटी का ग्रेटर नोएडा में विशाल कैंपस है। यूनिवर्सिटी का दावा है कि 40 देशों के 40 हज़ार छात्र उसके यहां पढ़ते हैं। यह यूनिवर्सिटी पहले भी विवादों में रही है। फिर भी इसे अगर एआई समिट में हिस्सेदारी की अनुमति मिल गई तो इसके पीछे कारण भाजपा में उसके उच्चस्तरीय संपर्क हैं। विवि भाजपा के कई बड़े नेताओं को सम्मानित कर चुकी है। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि उसे देश की प्रतिष्ठा को डुबोने का अधिकार मिल जाए।

गलगोटिया का कुत्ता लांछित भारत की एआई सत्ता

भारत का आम नागरिक अभी भी नहीं जानता कि एपस्टीन फ़ाइल्स है क्या? भारतीय समाज का एक बड़ा तबका तो आज भी पांच किलो अनाज की फिक्र करता है. इस एपस्टीन फ़ाइल्स पर बौद्धिक समाज का प्रतिरोध ज़रूर देखने को मिला है, जो अपने भारतीय संस्कृति व सभ्यता पर गर्व करता है. इस देश का नाम आने से बहुत आश्चर्य हुआ है. सवाल यह भी हो रहे हैं कि भारत दुनिया में क्या ऐसी ही सभ्यता के लिए अब जाना जाएगा? एपस्टीन फ़ाइल्स निःसंदेह सुनामी सी आई है जो मी टू के बाद जंगल में आग की तरह लोगों में बहस के लिए विवश की है. इसके कारण कितने उलटफेर विश्व भर में दिखेंगे, यह कहना आज मुश्किल है. भारत को ज़रूर अपने साभ्यातिक छवि के लिए आज विचार करना है क्योंकि यह देश ब्रह्मचर्य और त्याग के लिए जाना जाता है. हमारे ऋषि-मुनियों की छवि के लिए जाना जाता है जो अपने तेज के लिए जाने जाते रहे हैं. यदि हम अपने पूर्वजों पर गर्व कर रहे हैं तो हमारा भी आचार-विचार इस प्रकार का होना ही चाहिए कि हम किसी के पूर्वज के रूप में आदर प्राप्त करते हुए समरण किए जाएँ.

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
लेखक एनएचआरसी (इण्डिया) में स्पेशल मॉनिटर व केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

चीन से एक कुत्ता लाया गया. यह कुत्ता एक ऐसे जगह प्रदर्शित किया गया जहाँ भारत अपने ऊपर गर्व करने वाला था. जी-20 सम्मेलन के पश्चात् आई समिट दिल्ली का एक ऐतिहासिक आयोजन भारत दिल्ली में आयोजित किया. इसमें एपस्टीन फ़ाइल की वजह से पहले किरकिरी हुई. इसकी वजह थी एपस्टीन फ़ाइल से बदनाम हुए बिल गेट्स जिन्हें अपने देशों में आजकल बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उनकी पत्नी तक उन्हें दरिंदा बताया. उस बिल गेट्स का भारत में एआई समिट में की-नोट स्पीकर के रूप में आगमन और उसकी उपस्थिति भारतीय बौद्धिक समाज के गले से नहीं उतर रही थी. एपस्टीन फ़ाइल में दुनिया के ऐसे नामों का ज़िक्र आया जिससे बहुत से इस्तीफे हुए. कई जगह की सरकारें हिल गयीं. कई जगह तो खूब प्रदर्शन जैसे-जैसे नाम प्रकाश में आने लगे, रोष के रूप में हुए. जैफरिन एपस्टीन यौन अपराधी रहा है और उसके कारनामे आजकल चर्चा के केंद्र में है. भारतीय नाम भी आये और उसमें भी एक मंत्री और एक विक्टिम के रूप में महिला का नाम भारतीय सभ्यता को हिला दिया.

भारत का आम नागरिक अभी भी नहीं जानता कि एपस्टीन फ़ाइल्स है क्या? भारतीय समाज का एक बड़ा तबका तो आज भी पांच किलो अनाज की फिक्र करता है. इस एपस्टीन फ़ाइल्स पर बौद्धिक समाज का प्रतिरोध ज़रूर देखने को मिला है, जो अपने भारतीय संस्कृति व सभ्यता पर गर्व करता है. इस देश का नाम आने से बहुत आश्चर्य हुआ है. सवाल यह भी हो रहे हैं कि भारत दुनिया में क्या ऐसी ही सभ्यता के लिए अब जाना जाएगा? एपस्टीन फ़ाइल्स निःसंदेह सुनामी सी आई है जो मी टू के बाद जंगल में आग की तरह लोगों में बहस के लिए विवश की है. इसके कारण कितने उलटफेर विश्व भर में दिखेंगे, यह कहना आज मुश्किल है. भारत को ज़रूर अपने साभ्यातिक छवि के लिए आज विचार करना है क्योंकि यह देश ब्रह्मचर्य और त्याग के लिए जाना जाता है. हमारे ऋषि-मुनियों की छवि के लिए जाना जाता है जो अपने तेज के लिए जाने जाते रहे हैं. यदि हम अपने पूर्वजों पर गर्व कर रहे हैं तो हमारा भी आचार-विचार इस प्रकार का होना ही चाहिए कि हम किसी के पूर्वज के रूप में आदर प्राप्त करते हुए समरण किए जाएँ.

इस एपस्टीन फ़ाइल्स के अलावा भारत में एआई समिट इस बीच दिल्ली में आयोजित हुई. पाँच दिन चलने वाले इस सम्मेलन में देशों की सरकारों, अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, उद्योग, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं. कृषि व खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, डिजिटल ढाँचा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए यह समिट आयोजित हुई है. यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेस ने इस

सम्मेलन के सन्दर्भ में कहा है कि हमें साझा समझ बनानी होगी ताकि हमारे मज़बूत सुरक्षा ढाँचे तैयार हों. जनहित में नवाचार को बढ़ावा मिले. सहयोग मज़बूत हो. सबसे अच्छी बात यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन-2026 में विश्व की प्रदर्शनी की शुरुआत ऐसे नवाचारी तकनीकी समाधानों के प्रदर्शन से हुई, जो लोगों तक सहायता पहुँचाने की प्रक्रिया का कुशल एवं बेहतर स्वरूप दर्शाती है. भारत का भारत मंडपम इसके लिए खूब सजा. भारत अपनी ओर से प्रदर्शन के लिए तैयार हुआ. खूब अच्छे मन से भारत ने हमारे देश के नवाचारों व स्टार्टअप को आमंत्रित किया. शैक्षणिक संस्थानों को आमंत्रित किया. इस प्रदर्शनी में भारत की कई युनिवर्सिटी और आईआईटीज की अभिरुचि देखी गयी. निःसंदेह यह विश्व में भारत की चर्चा के लिए आयोजित समिट थी किन्तु अब इस देश की बदनामी से भी यह समिट जानी जाएगी.

गलगोटिया विश्वविद्यालय ने जो भारत की प्रतिष्ठा को तार-तार कर दिया उससे भारत शर्मिन्दित हुआ है. सबसे पहली बात यह है कि यदि हमारे इनोवेशन नहीं हैं तो उसे अपना बताना नहीं चाहिए. भारत में कट-कॉपी-पेस्ट की रिसर्च, जो नवाचार हैं उसमें भी कोई न कोई नक़ल, ऐसे ही पेपर्स का पब्लिकेशन है जो खूब भारतीय मुद्रा देकर प्रकाशित किया जाता है. प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने रैंकिंग के लिए इतना परेशान है कि उन्हें बस अपनी वाहवाही करवानी है और खूब अकूत धन देकर स्कोपस, एमडीपीआई में प्रकाशन करवाती हैं. खूब अकूत धन उगाही के लिए हमारे भारतीय छात्रों व शोध अध्येताओं को रिझाती हैं. यदि गलगोटिया का कुत्ता जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया था वह इस समिट में आँखों में धूल झोंकर इनोवेशन के नाम पर समिट की यात्रा पास कर लेता तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बल्ले-बल्ले हो जाती और इसके माध्यम से बहुत से एडमिशन मुह मांगी रकम पर होते लेकिन पोल खुल गयी. गलगोटिया का कुत्ता चीन का निकला जिसे गलगोटिया ने अपना इनोवेशन बताया था. जिसका नाम नेहा सिंह ने रोबो डॉग को ओरायन बताया. भारत में एआई पर हुए निवेश व चोरी दोनों पकड़ी गई. एआई डॉग चीनी रोबोट था जिसे प्रो. नेहा ने अपना बताया.

देश में अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची. भारतीय लोगों को इस यूनिवर्सिटी ने लज्जित किया और देश की छवि को बर्बाद किया. भारत की प्राइवेट यूनिवर्सिटी को क्या ऐसे कृत्यों से बचना नहीं चाहिए? गलगोटिया को समिट छोड़कर भागना पड़ा. अपने दावे के लिए फिर से नया झूठ गढ़ना पड़ा. इस समिट के सूत्र शब्द थे सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय लेकिन अब इसमें दो शब्द और जुड़ गए गलगोटिया के किस्से जुड़ने से सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, भारत विश्व से लुकाय. लुकाय का अर्थ मुह छिपाना होता है. यह सम्मेलन 20 से ज़्यादा राष्ट्राध्यक्षों, 60 मंत्रियों और 500 अंतर्राष्ट्रीय एआई प्रमुखों की एक साथ भागीदारी का साक्षी बन रहा है, उनके सामने भारत की किरकिरी बिल्कुल उचित नहीं है.

भारत सरकार की अपेक्षाओं पर एक तरह से पानी फेरने का काम हुआ है. भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें डर नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है. हमारे पास प्रतिभा भी है, ऊर्जा क्षमता भी है और नीति स्पष्टता भी है. आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस समिति में 3 भारतीय सोसायटी ने अपने एआई मॉडल और ऐप्स लॉन्च किए हैं. ये मॉडल, हमारी युवा पीढ़ी को दिखाते हैं और भारत जो सोल्यूशंस दे रहा है, उसकी गहराई और विविधता का भी दर्शन है. यह सभी दावे तब फेल हो जाते हैं जब गलगोटिया का कुत्ता विमर्श के केंद्र में आ जाता है.

आवश्यकता इस बात की है कि हम भारतीय जो बौद्धिक वर्ग है खासकर वह भारत की प्रतिष्ठा को गिराए नहीं अपितु भारत की बनी हुई इज्जत को और बढ़ाये. हमारे देश में ऐसे अनेक कीर्तिमान हैं लेकिन इस बार जो देश को लांछन मिला है वह भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा.

बजट 2026
डॉ. सत्येन्द्र किशोर मिश्र
प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय

कृषि को ठोस बुनियाद तथा वित्तीय बोझ के साथ संतुलन

पिछले वर्ष की तुलना में ग्यारह फीसद बड़ा, वर्तमान मोहन सरकार का तीसरा बजट कृषि क्षेत्र की ठोस बुनियाद तथा बढ़ते वित्तीय बोझ के साथ समष्टि आर्थिक संतुलन साधते हुए तीव्र औद्योगिक विकास की चुनौतियों के मध्य विकसित मध्यप्रदेश का मंसूबा रखता है। किसान कल्याण वर्ष में गरीब, युवा, नारी, किसान, आधारभूतढ़ांचा तथा औद्योगिक निवेश (ग्यानी) पर केन्द्रित मध्यप्रदेश का समावेशी तथा सर्वस्पर्शी रोलिंग बजट 2026-27 आगामी तीन वर्षो में राज्य के सामाजिकार्थिक विकास की दूरदृष्टि रखता है। भारतवर्ष में क्षेत्रफल में दूसरा, आबादी में पांचवा, युवा आबादी में तीसरा सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद देश की जीडीपी में मध्यप्रदेश का हिस्सा लगभग 3.6 फीसद, जबकि कर्ज में हिस्सा लगभग 4.9 फीसद है। वर्ष 2011-12 से भारतवर्ष की 5.6 फीसद की अपेक्षा मध्यप्रदेश की में जीएसडीपी में 6.8 फीसद बढ़ोत्तरी के बावजूद प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर मध्यप्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय रू.1,69,050 है, जो देश भर की प्रतिव्यक्ति का लगभग तीन चैथाई है। मध्य प्रदेश औद्योगिक तथा व्यावसायिक निवशों को बढ़ावा देकर राज्य की सामाजिक तथा आर्थिक दशा में बदलाव हेतु बजट से ढ़ेरों उम्मीदों हैं।

विगत डेढ़ दशक मेंकृषि तथा संबंधित क्षेत्र के उत्पादन में भारतवर्ष में मध्यप्रदेश का हिस्सा 3.6 फीसद से बढ़ाकर लगभग पांच फीसद पंहुच गया है। भारत में मध्यप्रदेश आज उत्पादन के मामले में दलहन में प्रथम, तिलहन तथा गेहूं में द्वितीय, दुग्ध में तृतीय स्थान रखने का साथ अन्य कृषि उत्पादन में एक महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है। सोयाबीन का लगभग 35 फीसद उत्पादन अकेले मध्यप्रदेश में होता है। देश में सर्वाधिक खाद्यान्न भण्डारण क्षमता के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र लगभग 43 फीसद है। बजट, कृषि क्षेत्र में डिजिटल, ई-सेवा सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग को बढ़ावा देते हुए संबंधित क्षेत्रों उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए विशेष प्रयास के जरिए किसान कल्याण पर केन्द्रित है। कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में तीव्र विकास तथा ढ़ेरों उपलब्धियों के बावजूद मध्यप्रदेश देश के अग्रणी आर्थिक राज्यों में नहीं है।

बजट में गरीब कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक वर्ग, विमुक्त तथा अर्द्ध-विमुक्त घुमक्कड़ सहित दिव्यांगजन तथा वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिकार्थिक सुरक्षा, आय एवं रोजगार सृजन, शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों में व्यय हेतु बजट में प्रावधान है। युवा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयीन शिक्षा से लेकर उच्चशिक्षा तक गुणवत्तापूर्ण रोजगारोन्मुखी शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु बढ़े आवंटन का प्रावधान बजट में है। नारी कल्याण हेतु महिलाओं के पोषण, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, सशक्तिकरण हेतु बजट मे कुल रू.1,27,555 करोड़ आवण्टन का प्रस्ताव है।

कृषि क्षेत्र की अपनी सीमाएं हैं, आर्थिक क्षेत्र में क्रान्तिकारी तथा बुनियादी बदलाव हेतु मजबूत तथा सक्षम आधारभूत संरचना के साथ उद्योग की जरूरत है। वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश को दो ट्रिलियन डॉलर अर्थात 250 लाख करोड़ की अर्थव्यस्था के साथ प्रतिव्यक्ति आय रूपये बाईस लाख पैंतीस हजार तक पहुॅचाने की दृष्टि बजट में है। उत्तम तथा सक्षम आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु 40 बृहद्, 60 मध्यम तथा 273 लघु सिंचाई निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कर नयी परियोजनाओं हेतु रू.14,742 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु नल कनेक्शन तथा हैण्डपंपों में आवण्टन बढ़ाया गया है। आधारभूत संरचना में सुधार हेतु साथ ही सड़क निर्माण, मरम्मत तथा उन्नयन, ग्रामीण सड़क निर्माण, पुलों का निर्माण पर भी आवण्टन बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को गति देने का संकल्प है। ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बिजली संयंत्रों की स्थापना तथा क्षमता में वृद्धि के साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के उत्पादन तथा उपयोग पर जोर है। 2025 उद्योग तथा रोजगार वर्ष था, जिस दौरान उद्योग कान्क्लेबों तथा सम्मेलनों के आयोजन से तैंतीस लाख करोड़ रूपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें लगभग साढ़े आठ लाख करोड़ रूपये के औद्योगिक विकास प्रस्तावों पर कार्य आरंभ भी हो चुके हैं। औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु अड़तालीस औद्योगिक पार्को तथा विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोरों का निर्माण प्रस्तावित है। निवेश तथा औद्योगीकरण कार्यो हेतु रू.5,957 करोड़ का प्रावधान है। संभवतः ग्यानी केन्द्रित बजट इस मकसद को पूरा कर सकेगा।

बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) रू.18,48,274 करोड़ रहने का अनुमान है जो विछले बजट से 10.69 फीसद अधिक है, तथा पूॅंजीगत परिव्यय जीएसडीपी का 4.8 फीसद है। यह सरकार की आर्थिक विकास रणनीति में बदलाव के जरिए औद्योगीकरण की तत्परता दिखाती है। मध्यप्रदेश सरकार को कर्ज के बढ़ते बोझ का भी सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2026-27 के अंत तक कर्ज बोझ बढ़कर जीएसडीपी का 32 फीसद तक पहुॅंचने का अनुमान है, जो अभी वित्तीय अनुशासन की सीमा के अन्दर तथा अनेक राज्यों की अपेक्षा कम अवश्य है, परन्तु इसे नियंत्रण में रखना जरूरी है। पूंजीगत परिव्यय ही बुनियादी परिसंपत्तियों के निर्माण की प्राथमिकता को दर्शाता है। साथ ही राजस्व व्यय में लगातार बढ़ोत्तरी पर नियंत्रण जरूरी है, यह बजट के सम्मुख महत्वपूर्ण चुनौती थी।

बजट में राजकोषीय घाटा रू.71,460 करोड़ अर्थात जीएसडीपी का 3.87 फीसद है, जो कि विगत दो बजट वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा रू.74,323 करोड़ अर्थात जीएसडीपी का 4.45 फीसद तथा बजट वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा रू.62,564 करोड़ अर्थात जीएसडीपी का 4.1 फीसद से काफी कम तथा नियंत्रण में है; यह वित्तीय अनुशासन की परिधि में भी है। यह भारत सरकार के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम 2004 की सीमा में है।

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में, कृषि, सेवा तथा विनिर्माण क्षेत्रों का हिस्सा लगभग क्रमशः 44 फीसद, 33 फीसद और 23 फीसद है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का हिस्सा बढ़ाकर औद्योगीकरण की राह पर तेजी से बढ़ाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। औद्योगीकरण के जरिए ही मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को तेजी से बढ़ सकता है। यदि मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय तथा एसडीजीपी में चमत्कारिक बढ़ोत्तरी करनी है तो, औद्योगीकरण ही एकमात्र जरिया है। मध्यप्रदेश में विगत दो दशकों में ऊर्जा उत्पादन क्षमता 5,173 मेगावॉट से बढ़कर वर्तमान में 28,000 मेगावॉट से अधिक है, जबकि नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 270.47 फीसद वृद्धि के साथ मध्यप्रदेश बिजली में सरप्लस राज्य बना है। देश के कुल सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश 8.2 फीसद का योगदान के साथ चैथे स्थान पर है। मध्यप्रदेश की आर्थिक संरचना भी औद्योगीकरण की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत तथा संभावना दिखाती है। यद्यपि मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन दिखे भी हैं, परन्तु अभी और भी बदलाव की जरूरत है। मध्यप्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में गिरावट जबकि द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि के संकेत भी है, परन्तु पर्याप्त नहीं है। औद्योगीकरण हेतु जरूरी प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधनों सहित ईंधन, खनिज, कृषि तथा जैव विविधता में समृद्ध होने के बावजूद वर्तमान में मध्य प्रदेश की एसजीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कम है, जो आर्थिक विकास के मापदण्ड पर उचित नहीं है।

मध्यप्रदेश सरकार का यह बजट सामाजिकार्थिक लक्ष्यों को साधते हुए तीव्र औद्योगिक विकास की राह में बढ़ने को संकल्पित है। सक्षम आधारभूत ढ़ांचा निर्माण पर जोर, औद्योगिक विकास को समर्थन एवं प्रोत्साहन के साथ-साथ सरकार की सामाजिकार्थिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए बजट 2026-27 के प्रावधान विकसित मध्यप्रदेश की संकल्पनो को साकार बनाने में कामयाब होंगे। बजट का मूल्यांकन ही इस बात पर होगा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश किस तरह से सक्रिय भूमिका निभा सकेगा।

त्वरित युग की धीमी संवेदनाएँ

दृष्टिकोण

तनुजा चौबे
लेखक साहित्यकार हैं।

समय का वेग अत्यंत प्रबल होता है। परिवर्तन को स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि परिवर्तन की गति और समय की गति समानांतर चलती हैं। डिजिटल क्रांति ने जीवन में व्यापक परिवर्तन ला दिया है। इसका विस्तार हर क्षेत्र में हुआ है, और संवाद के साधनों में तो विशेष रूप से। आज संवाद अत्यंत सरल और त्वरित हो गया है। एक क्लिक में संदेश पहुॅंच जाता है, जो बीते युग में महीनों या दिनों में पहुँचता था। वीडियो कॉल, लैपटॉप, फ़ोन आदि के माध्यम से दूरी का एहसास भी कम हो गया है। रिश्ते मानो एक छोटे-से बॉक्स में सिमट गए हैं। भावनाओं को अब लंबे वाक्यों में नहीं, बल्कि एक छोटे-से इमोजी से भी व्यक्त कर दिया जाता है।

परंतु विचारणीय प्रश्न यह है कि इस तीव्र रफ्तार में कहीं संवेदनाएँ क्षीण तो नहीं होती जा रहीं? जीमेल, इंस्टाग्राम आदि अनेक साधन संवाद के लिए उपलब्ध हैं। दूरी अब कोई मायने नहीं रखती; संवाद तात्कालिक हो गया है। किंतु संवाद की गहराई और भावनाओं की अभिव्यक्ति कहीं न कहीं कम होती प्रतीत होती है। इसे पत्र-लेखन द्वारा पुर्नस्थापित किया जा सकता है।

पत्र केवल शब्दों से भरा कागज़ नहीं होता, बल्कि वह संपूर्ण संवाद को भावनाओं सहित प्रेषित करता है। वह हृदय की ऊपरी सतह से नहीं, उसकी गहराइयों से अभिव्यक्त होता है। जब पत्र किसी के पास पहुँचता है, तो पढ़ने वाला भी तात्कालिक उत्तर नहीं देता, बल्कि आत्ममंथन करके प्रत्युत्तर देता है। पत्र लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों भावनात्मक आत्मसंतुष्टि से गुजरते हैं, जिससे एक ऐसा बंधन बनता है, जो डिजिटल माध्यम से संभव नहीं।

सुबह के 'गुड मॉर्निंग' और रात के 'गुड नाइट' संदेश, जो कई बार एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक घूमते हुए फिर वहीं लौट आते हैं, अभिवादन की औपचारिकता मात्र बनकर रह जाते हैं। उनमें भावनाओं की गहराई नहीं होती। इसके विपरीत, यदि सचमुच किसी तक अपनी भावनाएँ पहुँचानी हों, तो पत्र-लेखन एक सशक्त माध्यम है, जो संबंधों में ठहराव लाता है। पत्रों को सहेजकर रखा जा सकता है; वे कभी डिलीट नहीं होते। समय बीत जाने के बाद जब उन्हें पढ़ा जाता है, तो वही भावनाएँ पुनः जीवित हो उठती हैं। कागज़ को स्पर्श करते ही स्मृतियाँ पुनर्जीवित होकर जीवन में नई ऊर्जा भर देती हैं। डिजिटल पीढ़ी ने न डाकिए की आहट सुनी, न उसकी प्रतीक्षा का आनंद जाना। प्रतीक्षा का अनुभव उनके हिस्से में कम आया है, जिससे धैर्य की कमी परिलक्षित होती है। त्वरित उत्तर की आकांक्षा संबंधों के भविष्य पर भी प्रभाव डालती है। यदि मोबाइल पर किसी की नाराज़गी या दो व्यक्तियों के बीच विवाद हो और उसे त्वरित संदेशों से सुलझाने का प्रयास किया जाए, तो कई बार बात सुलझने के बजाय और उलझ जाती है। त्वरित संवाद कभी-कभी स्थिति को और बिगाड़ देता है।

पत्र-लेखन केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि आशा, उम्मीद और स्वप्नों को पूर्णता देने का माध्यम भी है। अनेक महान रचनाकारों ने समय-समय पर अपने पत्रों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। अनेक पत्र इतिहास, साहित्य और समाज के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुके हैं।

डिजिटल संवाद नकारात्मक नहीं है। इसके माध्यम से जीवन में सुगमता और समय की बचत हुई है। किंतु आवश्यकता हर युग में संतुलन की होती है। पत्र-लेखन केवल शब्दों को सजाने की कला नहीं, हमारी परंपरा भी है—और परंपरा सदैव संस्कृति से जुड़ी होती है। कभी-कभी विशेष अवसर पर लिखा गया पत्र संबंधों में गहराई और स्थायित्व दोनों ला सकता है। शिक्षण संस्थानों में पत्र-लेखन को पुर्नस्थापित किया जाना चाहिए। यह गति का विरोध नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी में संवेदनाओं के बीज रोपने का प्रयास है। उन्हें यह समझना होगा कि जब शब्द कागज़ पर अपना अस्तित्व ग्रहण करते हैं, तो वे केवल शब्द नहीं रहते—वे समय के वेग से आगे निकल जाते हैं। वे किसी समय-सीमा में बंधते नहीं, बल्कि युगों तक स्मृति बनकर जीवित रहते हैं।

इस तनावपूर्ण जीवन में, जहाँ मनुष्य मशीनों के साथ मशीन-सा होता जा रहा है, कभी इस आक्रांत ध्वनि से बाहर निकलकर कलम उठाएँ और पत्र लिखें। अपने मन से संवाद करें। अंतर्सुप्त भावनाओं को जागृत करें। संभव है, मन की हर संवेदना पोषित हो और आत्मा में नवसंचार हो। यही नवसंचार डिजिटल युग में भी मानवीय संवेदनाओं को जीवित रखकर जीवन में संतुलन बनाए रख सकता है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

जवाहर चौधरी
लेखक व्यंग्यकार हैं।

बहारों फूल बरसाओ

लोगों ने देखा कि राजा भ्रमण पर है! राजा लोग प्राचीन काल से ही भ्रमण के आदी रहे हैं। जब उनके पास करने को युद्ध भी नहीं रहता, तो वे प्रायः भ्रमण किया करते हैं। भ्रमण में 'भ्रमण' के अलावा उन्हें कुछ करना नहीं होता; जो भी करना होता है, रियाया को करना पड़ता है। राजकाज में आज भी भ्रमण का बड़ा महत्व है, बस इसे एक अच्छा सा नाम देना होता है– 'देश जोड़ो यात्रा', 'जागरण यात्रा', कभी 'सत्ता का सलाम' तो कभी 'हुकूमत की हेलो'। कभी 'शहीदों की याद में' तो कभी 'संग्रामियों के स्मरण में'। नाम कुछ भी हो सकता है, मूल बात है कि राजा भ्रमण पर है।

लोगों में जयकार के जीन्स वंशानुगत हैं, सो आवाजें आने ही लगती हैं। फूल बरस रहे हैं, राजा भ्रमण पर है। दीन-हीन गरीबों-लाचारों को मुख्य मार्ग से दूर रहने की फटकार है, राजा भ्रमण पर है। साथ चलता-फिरता दरबार है, राजा भ्रमण पर है। सोना-चाँदी, नकद सब स्वीकार है, राजा भ्रमण पर है।

लेकिन भ्रमण जरा लंबा हुआ तो राजा बोर होने लगा। उसने राजधानी वापस लौटने की इच्छा व्यक्त की। बात दरबारियों में फैली तो राजा के मनोरंजन की व्यवस्था पर विचार हुआ। स्थानीय स्तर पर एक बैंड प्रसिद्ध था, उसे बजाने वाले पीढ़ियों से बजा रहे थे। तत्काल कोई उपाय नहीं देख उन्हें ही पेश किया गया। बैंड वाले चतुर थे, उन्होंने बजाया– 'बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है...'। राजा को अच्छा लगा, उसने दोबारा सुना। और अच्छा लगा, और सुना। और-और अच्छा लगा, और-और सुना। उत्साहित बैंड वाले हर बार पहले से बेहतर बजाते।

राजधानी लौटते हुए राजा ने सारे बैंड वालों को अपने साथ ले लिया। बाजों के कारण भ्रमण उत्सव 'महाउत्सव' में बदल गया। राजा जिधर से गुजरता, स्थानीय बैंड वाले साथ हो जाते। सबके सुरों में एक ही राग होता– 'बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है...'।

राजधानी पहुँचते-पहुँचते राजा के साथ बैंड वालों की बहुत बड़ी संख्या हो गई। राजा को बैंड के गीत 'बहारों फूल बरसाओ...' का नशा सा हो गया। प्रसन्न राजा बैंड वालों को सुविधाएँ और इनाम देता, जिसे देख उपेक्षित सिपाही अपने को अपमानित समझने लगे। कुछ ही दिनों में खिन्न सिपाही आधा-अधूरा, जितना मिला उतना वेतन लेकर लौटने लगे। सेना की संख्या तेजी से कम होने लगी। इधर राजा के बैंड-प्रेम की चर्चा फैली। दूर-दूर से बैंड वाले लगातार राजधानी पहुँच रहे थे। सिपाहियों से खाली हुई जगह बैंड वालों से भरने लगी।

तभी राजा को सूचित किया गया कि सिपाही जा चुके हैं और सेना लगभग समाप्त हो चुकी है। राजा क्रोधित हुआ। राजा 'राजा' होता है, गलती अगर अपनी हो तब भी वह दूसरों पर क्रोधित हो सकता है। सिपाहियों को ससम्मान वापस लाने के लिए कहना उसे अपना अपमान लग रहा था। इच्छा तो उनका सिर कलम कर देने की हो रही थी, पर इस काम के लिए भी सिपाही होने चाहिए थे। अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने बैंड वालों को सिपाही की वर्दी पहना दी। अब बैंड वाले सिपाही थे, या यों कहें कि सिपाही बैंड वाले थे। हालाँकि बैंड वाले, बैंड वाले ही थे, लेकिन वे सिपाही थे। उन्हें वेतन और ओहदा सिपाही का मिल गया था; उनके लिए मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए। वे अभी भी 'बहारों फूल बरसाओ...' बजा रहे थे। पहले यह एक धुन या गीत था, अब सर्वसिद्धि मंत्र मानकर श्रद्धा से बजा रहे थे। राजा को पहले से ज्यादा आनंद आने लगा।

राजधानी में बैंड संस्कृति की जड़ें तेजी से जमने लगीं। हर मातहत अपने अधिकारी को बैंड सुनाने लगा। अधिकारी भी बैंड के आदी हो गए; बिना बाजा सुने वे कोई निर्णय नहीं लेते। उन्हें काम से अधिक बैंड पसंद था। दरअसल बैंड-वादन को ही अब काम का दर्जा मिल गया था। विवाह योग्य कन्याओं के पिता बैंड-वादन की प्रतिभा भाँप कर ही वर का चुनाव करने लगे। सरकारी बैंड में बजाने वाले मोटा दहेज माँगते, और उन्हें मिलता भी! बैंड सामाजिक शिष्टता में अनिवार्य सा हो गया। खुशी हो या गम, दोनों में लोग कुशलतापूर्वक बैंड बजाते।

सब आनंदपूर्वक चल रहा था कि सूचना आई– पड़ोसी राज्य की सेना ने आक्रमण कर दिया है और वह राजधानी की ओर बढ़ी चली आ रही है। राजा ने तत्काल संकटकाल की घोषणा की और सिपाहियों को युद्ध के लिए कूच का आदेश दिया। 'मजबूरन' सिपाहियों को उस ओर जाना पड़ा। राजा पिछली विजय के कारण निश्चिंत था। रनिवास के कुछ जरूरी काम निपटा कर वह भी युद्ध के मैदान में पहुँचा। यह देखकर वह चौंक पड़ा कि शत्रु बढ़ा चला आ रहा है और उसके सिपाही बाजे बजा रहे हैं– 'बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है...!!!'

जीवन कौशल शिक्षा : आत्मबल की पाठशाला

भारत जैसे देश में, जहाँ आधी से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है, बच्चों और युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधे जुड़ा है। यदि आज की पीढ़ी भीतर से टूट रही है, तो कल का भारत कैसे खड़ा होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हर सात में से एक किशोर मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त है। अवसाद किशोरों में मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल हो चुका है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 7.3 फीसद बच्चे किसी न किसी मानसिक विकार से पीड़ित हैं। इन बच्चों में अवसाद, चिंता, व्यवहार संबंधी समस्याएँ और आत्म-हीनता सामान्य होती जा रही हैं।

विचार

संध्या राजपुरोहित

लेखक शिक्षकों व आदिवासी बच्चों के साथ जीवन कौशल शिक्षा के कार्य से सम्बद्ध है।

21 वीं सदी केवल तकनीकी विकास की सदी नहीं है, बल्कि यह मनुष्यता के सबसे कठिन इम्तिहानों की भी सदी बन चुकी है। आज हमारे बच्चे मोबाइल, इंटरनेट और सूचना के जंजाल में जी रहे हैं, परंतु भीतर से वे अकेलेपन, असुरक्षा और भय से जूझ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हुए हैं, पर प्रश्न यह उठता है कि क्या यह शिक्षा बच्चों को जीवन जीने का साहस भी दे रही है? क्या वह उन्हें केवल नौकरी के लिए तैयार कर रही है या जीवन के लिए भी तैयार कर रही है?

आज शिक्षा का अर्थ केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रह सकता। बच्चे गणित, विज्ञान और भाषा तो सीख रहे हैं, लेकिन यदि वे अपने भीतर उठते भावनात्मक तूफ़ानों को समझ ही नहीं पा रहे, तो यह शिक्षा अधूरी है। शिक्षा के साथ जीवन कौशल का समावेश अब कोई वैकल्पिक प्रयोग नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है।

भारत जैसे देश में, जहाँ आधी से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है, बच्चों और युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधे जुड़ा है। यदि आज की पीढ़ी भीतर से टूट रही है, तो कल का भारत कैसे खड़ा होगा?

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हर सात में से एक किशोर मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त है। अवसाद किशोरों में मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल हो चुका है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 7.3 फीसद बच्चे किसी न किसी मानसिक विकार से पीड़ित हैं। इन बच्चों में अवसाद, चिंता, व्यवहार संबंधी समस्याएँ और आत्म-हीनता सामान्य होती जा रही हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2022 एक और भयावह तस्वीर सामने रखती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। यह आंकड़ा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हमारे बच्चों पर मानसिक बोझ कितना भारी हो चुका है। हर दिन औसतन 35 से अधिक परिवार अपने घर का उजाला खो देते हैं।

इन आँकड़ों के पीछे केवल पढ़ाई का दबाव नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था छिपी है जो बच्चों को दौड़ना तो सिखाती है, थमकर साँस लेना नहीं सिखाती। आज का बच्चा तुलना में जी रहा है। अंक, रैंक, सोशल मीडिया पर 'परफेक्ट लाइफ' की तस्वीरें– इन सबके बीच वह स्वयं को कमतर समझने लगता है। धीरे-धीरे यह भावना तनाव, अवसाद और कभी-कभी आत्मघात की ओर धकेल देती है।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की चुनौतियाँ अलग हैं, पर अधिक गहरी हैं। नीति आयोग की 2017 की रिपोर्ट बताती है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय में विद्यालय छोड़ने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसका कारण केवल गरीबी या संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि वर्षों से जमी हुई यह सोच भी है कि 'हम पीछे हैं' या 'यह पढ़ाई हमारे लिए नहीं है।' यह आत्म-अस्वीकृति ही सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह बच्चे की चेतना को भीतर से तोड़ देती है।

शिक्षा मंत्रालय की यूडाइस रिपोर्ट 2021-22 भी यही संकेत देती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रॉपआउट दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। जब बच्चा स्वयं को शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ा नहीं महसूस करता, तो वह शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा मानना भी छोड़ देता है।

ऐसे समय में जीवन कौशल शिक्षा एक प्रकाशस्तंभ की तरह सामने आती है। जीवन कौशल वे क्षमताएँ हैं, जो बच्चे को केवल पढ़ा-लिखा नहीं, बल्कि समझदार और संवेदनशील इंसान बनाती हैं। आत्म-जागरूकता,

भावनात्मक संतुलन, संवाद की क्षमता, समस्या समाधान, निर्णय लेने की समझ, सहयोग और सहानुभूति–ये सभी जीवन कौशल बच्चों के भीतर वह ताकत पैदा करते हैं, जिससे वह जीवन की कठिन परिस्थितियों से टूटता नहीं, बल्कि लड़ता है।

यूनिसेफ और यूनेस्को की संयुक्त रिपोर्ट लाइफ स्कील एजुकेशन फार यूथ (2019) इस बात की पुष्टि करती है कि जिन विद्यालयों में जीवन कौशल आधारित शिक्षा दी जाती है, वहाँ बच्चों में तनाव, हिंसा और आत्मघाती प्रवृत्तियाँ कम होती हैं तथा आत्मविश्वास, संबंधों की गुणवत्ता और निर्णय क्षमता में सुधार होता है।

जीवन कौशल कोई अतिरिक्त विषय नहीं है। यह हर विषय की आत्मा है। गणित सोचने की स्पष्टता देता है, भाषा अभिव्यक्ति की शक्ति देती है, विज्ञान जिज्ञासा का द्वार खोलता है, और सामाजिक विज्ञान विवेक का विकास करता है। जब इन सभी विषयों में जीवन कौशल की चेतना जुड़ जाती है, तब शिक्षा केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि चेतना जगाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह नीति पहली बार शिक्षा को केवल परीक्षा प्रणाली नहीं, बल्कि मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखती है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक दक्षता नहीं, बल्कि नैतिकता, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करना भी है। नीति में स्पष्ट प्रावधान है कि विद्यालयों में सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा, समालोचनात्मक सोच, संवाद कौशल, कला, खेल और समुदाय आधारित शिक्षण को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चा केवल उत्तर याद न करे, बल्कि जीवन को समझे।

शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 तक देश के 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जीवन कौशल आधारित कार्यक्रमों को लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कई राज्यों में विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य सत्र, परामर्श व्यवस्था और जीवन कौशल प्रशिक्षण शुरू किए गए हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो-साइंसेज की रिपोर्ट बताती है कि जिन बच्चों को भावनात्मक शिक्षा और जीवन कौशल प्रशिक्षण मिलता है, वे तनाव और अवसाद से जल्दी उबरते हैं। उनके भीतर आत्म-नियंत्रण और आत्म-सम्मान की भावना मजबूत होती है। अध्ययन बताते हैं कि जीवन कौशल आधारित कार्यक्रमों से बच्चों के तनाव स्तर में औसतन बीस प्रतिशत तक की कमी आई है।

जब किसी बच्चे को यह सिखाया जाता है कि वह जैसा है, वैसा ही मूल्यवान है, असफलता जीवन की विराम रेखा नहीं बल्कि सीख की भूमिका है, और तुलना करने के बजाय स्वयं से आगे बढ़ना ही वास्तविक सफलता है, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। शिक्षा मंत्रालय की 2023 की समीक्षा रिपोर्ट बताती है कि देश के 65 फीसद सरकारी विद्यालयों में अब मानसिक स्वास्थ्य और जीवन कौशल से जुड़े कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं।

जीवन कौशल बच्चों को सिखाते हैं कि असहमति भी संवाद से सुलझाई जा सकती है कि जीवन समस्याओं से भागने का नाम नहीं, उनका समाधान खोजने की यात्रा है। यही शिक्षा बच्चों को गलत कदम उठाने से रोकती है, क्योंकि उन्हें जीवन में आशा दिखाई देने लगती है। माता-पिता अंक नहीं, आत्मबल को प्राथमिकता देंगे। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि जीवन देना है और जीवन कौशल उस जीवन की साँस हैं।

भोपाल का पहला डाकघर, इस विरासत को बचा लीजिए

धरोहर

सुनील कुमार गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

ज़रा कल्पना कीजिए कि मेरी तरह आप सुबह की सैर पर निकले हों और आपके कदम ऐसी जगह पर जाकर ठहर जाएं, जहां गुमनाम, चुपचाप से कोने में खड़ी इमारत टाइम मशीन की तरह आपको अतीत में ले जाए और कुछ बुदबुदाने लगे। अचानक वहां आपको 'हिन्दोस्तां ज़िन्दाबाद' के नारों की बुलंद गूंज सुनाई देने लगे और कुछ नौजवान अंग्रेजों के झंडे 'यूनियन जैक' को उतार फेंक अपना 'तिरंगा' फहराते हुए आजादी के तराने गाते-नाचते दिखने लगें। यह वो हक़ीकत है, जिसकी इबारत भोपाल में आजादी के मतवालों ने 15 अगस्त 1947 को इसी छोटी सी इमारत में लिखी थी और गिरफ्तार कर लिए गए, क्योंकि 15 अगस्त को भारत तो आज़ाद हो गया था, लेकिन भोपाल नहीं। भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला के सिपहसालार तिरंगा फहराने वाले जांबाजों को यहीं से मुश्कें बांध कर ले गए थे।

इस जगह पर यह घटना इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भोपाल में तिरंगा फहराना अपराध था। भोपाल रियासत के नवाब ज़ाहिरा तौर पर भारत में विलय का विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। 'तिरंगे' जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों को राज्य विरोधी माना जाता था। यही वजह है कि इसके कई नायक गुमनाम रह गए।

जी हां, हम बात कर रहे हैं भोपाल के जुमेराती इलाके में सिंधी मार्केट, जुमेराती और चौकी इमामबाड़ा को जोड़ने वाले तिराहे पर कोने में दुबकी छोटी सी इमारत में आज भी चलने वाले डाकघर की, जो अब उप डाकघर जुमेराती के नाम से जाना जाता है। यह डाकघर भोपाल का पहला डाक घर है, जहां उस दौर की आधुनिक सुविधाओं के साथ सुव्यवस्थित डाक व्यवस्था की बुनियाद पड़ी और नए सफरनामे की शुरुआत हुई। गुज़रे इतवार सैर का मुक़ाम यही वो डाकघर था, जिसके इतिहास को टटोलने और उस वक्त से जुड़े अहसासों को दर्ज करने की हमने कोशिश की।

इस डाकघर में आजादी के जश्न-जुनून और जुल्म की अपनी दास्तां तो रोचक-रोमांचक है ही, इसके साथ ही भोपाल में यह डाकखाना खुलने और उसके लिए जद्दोजहद की भी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। भोपाल के रियासत काल में आज की तरह कोई व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेंजर, टेलीग्राम, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म, ई-पोस्ट, ई-मनीआर्डर, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री जैसे साधन और सूचना-संचार का संसार तो था नहीं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक यहां कोई संगठित डाक व्यवस्था नहीं थी। शाही फरमान, सैन्य आदेश, दूसरे राजाओं-नवाबों को संदेश पैदल, घुड़सवारों-हरकारों और भरोसेमंद दूतों के जरिए ही भेजे जाते थे। आम-जनता के लिए ख़तो-किताबत की सहूलियत तो थी नहीं। अपने तरीके से संदेशों को भेजना-मंगाना तो रईसजादों या कहें सक्षम, समृद्ध लोगों के बस की ही बात थी।रियासत के काम को अंजाम देने के लिए रायसेन, गढ़ी, आंबापानी, बेगमगंज आदि स्थानों पर डाक चौकियां थीं। इन तक फरमान पहुंचाने के लिए हरकारे हुआ करते थे।

भोपाल गजेटियर के दस्तावेजों के मुताबिक 1818 में भोपाल रियासत के ब्रिटिशों की सरपरस्ती में आने के बाद यहां प्रशासनिक सुधारों काम शुरू हुआ और इस क़वायद के 12 साल गुजरने के बाद सन् 1830-40 के बीच भोपाल में रियासती डाक व्यवस्था की औपचारिक शुरूआत हुई।

वास्तव में भोपाल रियासत की बेगमों के शासनकाल में यहां डाक व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ज्यादा महत्व दिया गया। भोपाल रियासत की रीजेन्ट और नवाब सिकंदर जहां बेगम की (1845-1868) ने उस समय अपनी रियासत का पहला डाक टिकट तो जारी कर दिया, लेकिन डाक को लाने-लेजाने के ऊंट-घोड़े-हरकारे जैसे सभी साधन बहुत महंगे साबित हुए। यह स्थिति निरन्तर बनी रही। उधर अंग्रेज अपनी डाक व्यवस्था थोपने के लिए बार-बार सिकंदर जहां बेगम पर दबाव डाल रहे थे और कह रहे थे कि आपकी डाक व्यवस्था महंगी है, क्योंकि भोपाल में रेल्वे स्थापित नहीं है। इसलिए भोपाल रियासत अपना जारी किया हुआ डाक टिकट बंद करे या फिर उसकी रायल्टी अंग्रेज सरकार को दे। दोनों पक्षों के अड़े रहने के कारण इसका कोई समाधान नहीं निकल सका। पूरे मुल्क में डाक-दूरसंचार व्यवस्था मजबूत पकड़ के साथ ब्रिटिश इंडिया गर्वनमेंट संभाले हुए थी,उसकी यह आपत्ति थी कि डाक, रेलवे, सीमा शुल्क और कर आदि राजस्व संबंधी मामले ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। अभिलेखों से पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ देश की दूसरी रियासतों जैसे-इंदौर की होल्कर और ग्वालियर की सिंधिया रियासत के मुकाबले भोपाल रियासत बहुत पिछड़ी हुई और कमज़ोर थी। भोपाल को अपने वजूद को बरकरार रखने, वक्त के साथ चलने के लिए कई समझौते और संघर्ष करना पड़े।

अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि इसके बाद जब शाहजहां बेगम (1868-1901) भोपाल की नवाब बनीं तो

उन्होंने कलकत्ता जाकर वहां वायसराय लॉर्ड डरफन से भेंट की तथा दोनों के मध्य एक संधि हुई। संधि के दो प्रारूप तैयार किए गए। पहले प्रारूप में यह तय हुआ कि भोपाल रियासत की करेंसी समाप्त कर दी जाए, क्योंकि ब्रिटिश सिक्के अथवा नोट और भोपाल रियासत के सिक्के अथवा नोट की विनिमय दर में बहुत अंतर है। इसलिए यह संभव नहीं है कि भोपाल की करेंसी अन्य रियासतों में क्रय-विक्रय के काम में उपयोग की जा सके। इस संधि के मुताबिक भोपाल रियासत की करेंसी समाप्त कर दी गई और यहां ब्रिटिश करेंसी लागू हो गई।

दूसरी संधि का प्रारूप यह था कि भोपाल (1885) में रेलवे की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसलिए भोपाल को अपनी डाक व्यवस्था समाप्त कर ब्रिटिश इंडिया गर्वनमेंट की डाक योजना लागू की जाए। इस योजना को लागू करने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार एवं रेलवे के उच्चाधिकारियों का दल और ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट भोपाल आए। बेगम शाहजहां बहुत तरक्की पसंद, लेकिन ज़िद्दी स्वभाव की शासक थीं। उन्होंने एक शर्त यह भी रखी कि भोपाल के डाक टिकटों पर ब्रिटिश वायसराय या रानी विक्टोरिया के चित्र नहीं दर्शाए जाएंगे। यह शर्त बयां करती है कि अंग्रेजों का साथ भोपाल रियासत के लिए मजबूरी था, लेकिन वास्तव में उनसे कामकाजी रिश्तों भर का लगाव था। बेगम शाहजहां रियासत की पहचान पर खतरे को लेकर सजग और संजीदा थीं।

बहरहाल काफी जद्दोजहद के बाद सन् 1887 में भोपाल के व्यापारिक क्षेत्रों से जुड़े मोहल्ले जुमेराती में 'इम्पीरियल स्टेट पोस्ट ऑफिस' स्थापित किया गया, जिसके लिए भूमि ब्रिटिश सरकार ने भोपाल रियासत से खरीदी। इस ऐतिहासिक डाकघर की स्थापना के बाद इस पर ब्रिटिश सरकार का ध्वज 'यूनियन जैक' लहराया गया। यहां से भोपाल में सुव्यवस्थित डाक व्यवस्था की बुनियाद पड़ती है। उस समय पोस्ट मास्टर का पद बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति को दिया जाता था, क्योंकि नवाबी दौर में शासकों को डर रहता था कि कहीं कोई उनकी शिकायत तो ब्रिटिश सरकार को नहीं कर रहा है। जिन लोगों के पास चिट्ठी-पत्री, डाक अधिक संख्या में आती थी, उन्हें संदिग्ध नजरों से देखा जाता था और उन पर निगरानी बैठा दी जाती थी। उस समय गोपनीय पत्रों को भेजने से पहले शासन की अनुमति लेना पड़ती थी। इसलिए लोग पोस्ट मास्टर से अच्छे संबंध विकसित करते थे, ताकि उनके पत्र खोलकर नहीं पढ़े जाएं।

भोपाल गजेटियर के मुताबिक शाहजहां बेगम और उनके बाद सुल्तान जहां बेगम (1901-1926) के शासनकाल में डाकघरों की संख्या बढ़ी, डाक शुल्क तय हुए। जनता के लिए पत्र, मनीऑर्डर और नोटिस संभव हुए।

एक नजरिए से देखें तो यह डाकघर उस सफर की बुनियाद रहा, जहां से चलकर डाक व्यवस्था ने केवल तकनीकी इतिहास ही नहीं लिखा, बल्कि जन-जन तक सूचना का जरिया, सत्ता और नागरिक के बीच संवाद का जरिया बनी। जनता को अपनी अभिव्यक्ति का एक रास्ता मिला। डाकघर सामाजिक संपर्क के केन्द्र बन गए।

भोपाल के सबसे पहले और सबसे पुराने डाकघर के बाहर एक लालरंग का पोस्ट आफिस का डिब्बा आज भी लगा हुआ है। हालांकि व्हाट्सएप, ई-मेल के इस दौर में इसमें चिट्ठियां बहुत कम ही आती हैं। भोपाल के ऐतिहासिक महत्व का यह पोस्ट ऑफिस खुलता तो है, लेकिन पुरसाने हाल उजड़े हुए दयार जैसा है। चाय-पान की दुकानों का अतिक्रमण कैम्पस की बाउंड्री तोड़कर भीतर घुस गया है। कैम्पस में गंदगी और लंबी डोरी पर टंगे किसी के बहुत सारे कपड़े सूख रहे थे। गेट के बाहर दोनों ओर किसी धार्मिक समूह के झंडे टंगे हुए थे। पुराने भोपाल के सबसे व्यस्ततम बाजारों में शुमार जुमेराती में भीड़ तो बहुत रहती है, ट्रेफिक जाम भी खूब लगता है, लेकिन हर नजर से यह डाकघर छुप सा जाता है। इस ऐतिहासिक डाकघर के नजदीक तकरीबन 50 साल से किराना दुकान चला रहे क़ासिम अली कहते हैं, कि भोपाल के इस सबसे पुराने डाकघर में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को कुछ अधिकारी और आम लोग जुटते हैं और झंडा फहराकर जाने के बाद कभी सुध नहीं लेते। कुछ लोग कहते हैं कि यह राज्य संरक्षित इमारत है, लेकिन राज्य संरक्षण की सूचना देती कोई तख्ती तो हमें नहीं दिखाई दी और हालात भी ऐसे नहीं दिखे कि इस इमारत का कहीं, किसी भी तरह का कोई संरक्षण किया गया हो। भोपाल की यह विरासत को सरकार की नजरे इनायत की दरकार है, क्योंकि यह शर्म की नहीं, गर्व की विरासत है, क्योंकि पूरे भोपाल के साथ-साथ यहां भी 15 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मनाया था और सबसे पहले यहीं ब्रिटिश यूनियन जैक को हटा कर तिरंगा फहराया गया था। बताया जाता है कि उस वक्त भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला की पुलिस ने प्रजामंडल सरकार के नुमाइंदे रहे पं. चतुर नारायण मालवीय, भाई रतन कुमार जैसे कई युवा आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए थे। उनके नाम गजेटियर और प्रशासनिक दस्तावेजों में हो सकता है कि न मिलें, क्योंकि गजेटियर आमतौर पर प्रशासनिक घटनाओं का संक्षेप देता है और जनआंदोलन के व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं के नाम नहीं देता। दूसरी वजह यह भी है कि 1949 में भोपाल के भारत संघ में विलय के दौरान भोपाल रियासत की पुलिस कार्यवाही, एफआईआर और मजिस्ट्रेटी कार्रवाई का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया गया था। एक बार फिर दरकार इसे बचा लीजिए, सहेज लीजिए सजा और संवार लीजिए सरकार। यह हमारी विरासत-हमारी शान-हमारी पहचान है।

भारतीय कृषि के लिए नया 'अग्निपथ' तैयार

कृषि

निलेश देसाई

लेखक कृषि मामलों के जानकार हैं।

खेती केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता का आधार रही है और इसकी धुरी रही है - बीज। हजारों वर्षों से किसानों ने बीजों को चुना, सहेजा और साझा किया, जिससे जैव-विविधता का एक विशाल भंडार निर्मित हुआ, लेकिन 21वीं सदी में यह परंपरा एक कानूनी जुर्म में बदलती दिख रही है। केन्या और कोलंबिया ने जो चेतावनियां दी थीं, वे अब भारत के 'बीज विधेयक 2025,' 'यूरोपियन यूनियन' और अमरीका के साथ हुए व्यापार समझौतों तथा कृषि के डिजिटल रूपांतरण के चलते भारत के सामने खड़ी हो गई हैं। क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ अपनी ही जमीन पर, अपने ही पूर्वजों के बीज उगाना अवैध हो जाएगा?

वर्ष 2012 में केन्या ने अपने 'सीड्स एंड प्लांट वैरायटीज एक्ट' में संशोधन किया। इस बदलाव के पीछे कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों' का दबाव था। कानून ने प्रावधान किया कि बिना पंजीकरण और प्रमाणन के किसी भी बीज का आदान-प्रदान या बिक्री अपराध होगी, जिसके लिए 2 साल की जेल या भारी जुर्माने की व्यवस्था की गई। परिणामस्वरूप केन्या का छोटा किसान, जो सदियों से स्थानीय किस्मों पर निर्भर था, रातों-रात अपनी ही विरासत उगाने के अपराध में धर लिया गया।

कोलंबिया में भी यही हुआ। अमेरिका के साथ 'मुक्त व्यापार समझौते' की शर्तों को पूरा करने के लिए सरकार ने 'रेसोल्यूशन 970' के तहत किसानों का अनाज जब्त कर उसे नष्ट कर दिया। इन दोनों देशों ने एक ही सबक दिया - जब बीज पर कानून का पहरा बैठता है, तो किसान की आजादी और देश की खाद्य संप्रभुता दोनों मर जाते हैं।

भारत में प्रस्तावित 'बीज विधेयक 2025' पुराने 1966 के कानून को बदलने की तैयारी में है। सरकार का तर्क है कि यह कानून बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा और किसानों की आय बढ़ाएगा। हालांकि, इसकी परतों को उधेड़ने पर कुछ गंभीर चिंताएं सामने आती हैं। मसलन - विधेयक में व्यावसायिक बीजों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। यद्यपि किसानों को अपने उपयोग के लिए बीज बचाने की छूट है, लेकिन 'व्यावसायिक बिक्री' की परिभाषा इतनी जटिल हो सकती है कि छोटा किसान अपने पड़ोसी को बीज बेचने से पहले सौ बार सोचेगा।

विधेयक में नियमों के उल्लंघन पर रू. 50,000 से लेकर रू. 30 लाख तक के जुर्माने और जेल का प्रावधान है। यह कानून बड़ी बीज कंपनियों को 'शिकायतकर्ता' की भूमिका में लाकर छोटे किसानों को अदालतों में घसीटने का हथियार बन सकता है।

अभी, फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच हुए हालिया व्यापार अनुबंध ने भारतीय कृषि के लिए एक नया 'अग्निपथ' तैयार कर दिया है। अमेरिका का दबाव हमेशा से 'बौद्धिक संपदा अधिकारों' को सख्त करने पर रहा है।

इस अनुबंध से भारत के कुछ बड़े किसानों को अमेरिकी बाजार में पहुंच मिलेगी, लेकिन इसकी कीमत छोटे और मझोले किसानों को चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका से आने वाले सस्ते और सब्सिडी वाले कृषि उत्पाद (जैसे मक्का, सोयाबीन और डेयरी उत्पाद) भारतीय किसानों की घरेलू कीमतों को गिरा सकते हैं।

अमेरिका लंबे समय से भारत में 'जीन संवर्धित' (जीएम) बीजों के प्रवेश का रास्ता खोलने का दबाव बनाता रहा है। यदि इन अनुबंधों के प्रभाव में भारत अपनी नीतियों में ढील देता है, तो हमारे देशी बीजों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। भारत-अमरीका समझौते के करीब सालभर लटके रहने की वजह भी 'जीएम' उत्पादों को प्रवेश नहीं देने का यही विवाद था।

2026 के बजट में कृषि के डिजिटलाइजेशन और डिजिटल 'एग्री-स्टैक' के लिए अभूतपूर्व बजटीय आवंटन किया गया है। 'एग्री स्टैक' सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा 'डिजिटल फॉउन्डेशन' है जिसका उद्देश्य भारत में कृषि को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना और डेटा तथा डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके किसानों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करना है। हर खेत का अपना 'डिजिटल आईडी' और हर फसल की 'क्यूआर कोड' सुनने में तो आधुनिक लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपे खतरे को समझना जरूरी है।

जब किसान के खेत का पूरा डेटा (कौन सा बीज बोया गया, कितनी खाद डाली गई) डिजिटल सर्वर पर होगा, तो बड़ी बीज कंपनियां इस डेटा का उपयोग किसानों को लक्षित विज्ञापन देने या उन्हें अपनी विशेष किस्मों के जाल में फंसाने के लिए करेंगी। यदि 'बीज विधेयक 2025' में देशी बीजों पर कोई प्रतिबंध लगता है, तो 'डिजिटलाइजेशन' उस प्रतिबंध को लागू करने का सबसे प्रभावी हथियार बनेगा। 'सैटेलाइट इमेजिंग' और 'डिजिटल रिकॉर्ड्स' के जरिए यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि किस किसान ने 'अपंजीकृत' बीज बोए हैं।

अभी 27 जनवरी '26 को हुए 'मुक्त व्यापार समझौते' में यदि भारत 'यूरोपीय संघ' के साथ व्यापार के लालच में 'यूपीओवी' (इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ प्लॉन्ट्स) के मानकों को अपनाता है, तो हमारी 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (2001)' की वह धारा (धारा 39) खत्म हो जाएगी जो किसानों को बीज बेचने का कानूनी अधिकार देती है। यह भारतीय कृषि के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है।

'यूरोपीय संघ' के साथ की व्यापार वार्ताओं में अक्सर 'यूपीओवी' की सदस्यता की शर्त रखी जाती है। केन्या ने यही गलती की थी।

केन्या और कोलंबिया के उदाहरण हमें जगाने के लिए हैं। भारत को अपनी नीतियों में कानूनी कवच लगाना होगा। 'बीज विधेयक 2025' में यह स्पष्ट और अपरिवर्तनीय प्रावधान होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में किसान का बीज साझा करना 'जुर्म' नहीं माना जाएगा। सरकार को कॉर्पोरेट बीजों की बजाय 'सामुदायिक बीज बैंकों' को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। किसानों के डेटा पर पहला अधिकार किसानों का होना चाहिए, न कि बड़ी कंपनियों का। कृषि विश्वविद्यालयों को हाइब्रिड के बजाय देशी बीजों की उत्पादकता सुधारने पर शोध करना चाहिए।

भारत के सामने आज जो परिदृश्य है, वह केवल अर्थव्यवस्था का नहीं, बल्कि संस्कृति और अस्तित्व का है। केन्या में जो हुआ, वह कानून की एक भूल थी; भारत में जो होने जा रहा है, वह एक सचेत निर्णय होगा। यदि हम व्यापारिक समझौतों और 'डिजिटलाइजेशन' की चमक में अपने 'बीज' खो देते हैं, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों की 'खाद्य सुरक्षा' को कॉर्पोरेट तिजोरियों में गिरवी रख देंगे। समय की मांग है कि हम 'विकास' की ऐसी परिभाषा चुनें जिसमें किसान के हाथ में हल भी हो और अपनी मिट्टी का आजाद बीज भी। क्योंकि, जिस देश का बीज गिरवी होता है, उस देश की थाली कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। (सप्रेस)

नवीन फ्लोरिन ने दी,तीन सरकारी स्कूलों के बच्चों को आरओ की सौगात

देवास। अपने सामाजिक दायित्वों के तहत जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों को शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने के लिये मफतलाल समूह के नवीन फ्लोरिन उद्योग द्वारा सामाजिक संस्था 'एक्ट ईव फाउंडेशन' की पहल और समन्वय से जिले के तीन स्कूलों को आरओ भेंट किये है जिससे चार सौ से अधिक बच्चों को अब आर ओ का शुद्ध पानी मिलेगा । नवीन फ्लोरिन के अतुल मौर्य तथा एक्ट ईव फाउंडेशन के

मोहन वर्मा ने बताया कि ये आर ओ ग्राम खरपड़ी, बैरागढ़ तथा टोंक कला के माध्यमिक स्कूलों में भेंट किये गये । कार्यक्रम में अतिथि रूप में नवीन फ्लोरिन के श्री संजय सिंह एच आर हेड,शशिकांत पंवार, डॉ.अनंता शिंदे,रोटरी क्लब सहायक मंडलाध्यक्ष दिनेश कार्पेटर, संकुल प्राचार्य सुश्री नीता शर्मा उपस्थित थे । खरपड़ी में प्राचार्य खुर्शीद आलम खान ने बैरागढ में लोधी सर ने तथा टोंक कला में श्रीमती हँसा चौधरी ने अतिथियों का स्वागत तथा संचालन किया और नवीन फ्लोरिन उद्योग तथा 'एक्ट ईव फाउंडेशन' के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विष्णु आर्य, आलेख वर्मा, अभिषेक राठौर,अशोक शर्मा,राहुल परमार,रीना चौधरी, रितिका मजुमदार, मंगला पाठक, अनामिका टोप्पो, श्वेता तिवारी, ममता पाठक, मनोज उपाध्याय,रेखा परिहार सहित स्कूल स्टाफ व ग्रामवासी उपस्थित थे ।

10वीं के 15821 विद्यार्थियों ने 127 केंद्रों पर दी परीक्षा

बैतूल। माध्यमिक शिक्षा मंडल मप्र भोपाल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा-2026 के तहत गुरुवार को जिले में कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का प्रश्नपत्र शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जिनमें कुल 16260 परीक्षार्थी दर्ज थे। इनमें से 15821 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 439 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने 32 परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। परीक्षा में 2 नकल प्रकरण बने। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं हुई।

दो दिवसीय बैतूल प्रवास पर आएंगे सैनिक कल्याण संचालक, पूर्व सैनिकों से करेंगे संवाद

बैतूल। संचालक सैनिक कल्याण मप्र भोपाल ब्रिगेडियर अरुण नायर, सेना मेडल (से.नि.) 25 एवं 26 फरवरी को बैतूल, मुलताई और सारणी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर पूर्व सैनिकों, शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार 25 फरवरी को वे कारगिल चौक बैतूल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद शाम 4.30 बजे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में पूर्व सैनिकों, शहीदों की पत्नियों एवं उनके आश्रितों की समस्याएं सुनेंगे। ब्रिगेडियर नायर 26 फरवरी को सुबह 10.30 बजे ग्राम मोही, मुलताई में द्वितीय विश्वयुद्ध की वीर नारी से भेंट करेंगे। इसके पश्चात 11 बजे शासकीय अस्पताल परिसर स्थित ईसीएचएस कैंप, मुलताई में पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों से संवाद करेंगे।

नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अवमानना का केस रद्द

जबलपुर (नप्र)। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने बुधवार को नगर निगम भोपाल की आयुक्त संस्कृति जैन के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई निरस्त कर दी। एकलपीठ ने उन्हें अवमानना में दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई निर्धारित की थी। जिसके खिलाफ महिला आईएएस अधिकारी ने अपील दायर की थी। युगलपीठ ने अपील की सुनवाई के बाद एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए महिला आईएएस अधिकारी के पक्ष में राहतकारी आदेश जारी किए।

बिल्डिंग अनुमति कर दी थी निरस्त- गौरतलब है कि नगर निगम भोपाल के द्वारा मर्लिन बिल्डकॉन प्रा लि. कि श्यामला हिल्स स्थित नादिर कॉलोनी में स्थित उसकी 3520 वर्ग फीट में बिल्डिंग की अनुमति 28 अगस्त 2025 को निरस्त कर दी गयी थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका के लंबित रहने के दौरान नगर निगम ने विगत 18 जनवरी को बिल्डिंग का एक हिस्सा तोड़ दिया था। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नगर निगम की कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर एक्ट के तहत पारित दिशा-निर्देश के विपरीत पाते हुए मनमानी कार्यवाही किए जाने पर नगर निगम आयुक्त भोपाल संस्कृति जैन को तलब किया था।

धूमधाम से मनाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती

मराठा और कुंबी समाज ने निकाली रैली, मरीजों को बांटे अंकुरित अनाज

बैतूल। गुरुवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिला क्षत्रिय मराठा समाज और क्षत्रिय लोणारी कुंबी समाज संगठन द्वारा शहर में अलग-अलग स्थानों पर भव्य कार्यक्रमों और रैलियों का आयोजन किया गया। दोनों संगठनों द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम और शोभायात्राएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी हैं और कार्यक्रमों के जरिए समाजजनों को शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया गया है। क्षत्रिय मराठा समाज, बैतूल द्वारा सबसे पहले शिवाजी महाराज की प्रतिमा का विधिवत पूजन किया गया। इसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। यह शोभायात्रा शहर का भ्रमण करते हुए बैतूल गंज स्थित राधा कृष्ण धर्मशाला पहुंची। धर्मशाला में समाज के लोगों के लिए मंचीय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं, क्षत्रिय लोणारी कुंबी समाज संगठन ने सेवा कार्य के साथ अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। समाज के लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों और

उनके परिजनों को अंकुरित आहार का वितरण किया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी सांस्कृतिक भवन से एक विशाल रैली निकाली गई।

ऑडिटोरियम में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम- सांस्कृतिक भवन से शुरू हुई यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शिवाजी चौक पहुंची। यहां समाजजनों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद रैली का समापन ऑडिटोरियम में हुआ, जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में क्षत्रिय लोणारी कुंबी समाज संगठन के जिलाध्यक्ष प्रवीण ठाकरे, नगरपालिका अध्यक्ष पार्वती बारस्कर, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत वागद्रे और पूर्व संगठन अध्यक्ष दिनेश महस्की विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि, शिवाजी महाराज का जीवन पराक्रम, संगठन और स्वाभिमान की मिसाल है, जिससे हर पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए।

जिले में 14 मार्च को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन

लोक अदालत का एक ही सार, न किसी की जीत न किसी की हार

बैतूल। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 को जिला मुख्यालय जिला न्यायालय बैतूल के साथ-साथ सिविल न्यायालय आमला, भैंसदेही, मुलताई तथा ग्राम न्यायालय, श्रम न्यायालय तथा उपभोक्ता फोरम में किया जाएगा। उक्त लोक अदालत में न्यायालयों लंबित एवं राजीनामा योग्य समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना एवं क्षतिपूर्ति दावा, विद्युत अधिनियम, चैक बाउन्स, ट्रैफिक चालान एवं पारिवारिक व भरण-पोषण संबंधी वैवाहिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति व राजीनामा के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक ऋण वसूली, विद्युत के बकाया बिल, नगरपालिका के जल कर एवं दूरसंचार विभाग के टेलीफोन बिल के प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी आपसी सहमति व राजीनामा के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल ने सभी नागरिकों से अपील है कि वे अपने विवादों व प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराते हुए नियमानुसार छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि लोक अदालत से शीघ्र व सस्ता न्याय होता है। समय व धन की बचत होती है। कोर्ट फीस वापस होती है। इसके अतिरिक्त सौहार्द्र पूर्ण हल होता है तथा प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है, जो पक्षकार अपने प्रकरणों में राजीनामा कराने के इच्छुक है वह कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय बैतूल के साथ-साथ सिविल न्यायालय आमला, भैंसदेही तथा मुलताई में संपर्क कर सकते है।

विद्युत प्रकरणों में राजीनामा के संबंध में अधिकारियों के साथ हुई बैठक

14 मार्च को विद्युत प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण तथा पक्षकारों को विद्युत प्रकरणों में शासन द्वारा दी जाने वाली छूट प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल दिनेश चन्द्र थपलियाल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला न्यायालय में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में विद्युत प्रकरणों के न्यायाधीश एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश नारायण अहिरवार, जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय, महाप्रबंधक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बीएम बघेल, उप-महाप्रबंधक अभय कुमार गोप एवं योगेन्द्र चौधरी तथा विद्युत विभाग के पेनल अधिवक्ता तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चन्द्र थपलियाल द्वारा उपस्थित अधिकारियों को संमन्स की तामिली, पक्षकारों की उपस्थिति, प्रीसिटिंग बैठक तथा जमा की जाने वाली राशि के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए बिजली चोरी एवं बिजली के बकाया बिल आदि अधिक से अधिक लंबित एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों में राजीनामा सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करते हुए कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया।

अंचल से उठी आवाज़ ने छुआ राष्ट्रीय मंच

कैलाश प्रसाद अग्निहोत्री ने सुरेश चव्हाणके से की मुलाकात

बैतूल। जन परिषद के इंटर स्टेट कमेटी सचिव एवं पत्रकार कल्याण परिषद के बैतूल जिला अध्यक्ष, भौंरा निवासी वरिष्ठ पत्रकार कैलाश प्रसाद अग्निहोत्री ने दिल्ली में देश के चर्चित पत्रकार सुरेश चव्हाणके से भेंट कर पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और उसके सामाजिक दायित्वों पर सार्थक चर्चा की। वर्षों से अंचल की समस्याओं को मुखरता से उठाते रहे कैलाश प्रसाद अग्निहोत्री ने इस मुलाकात में ग्रामीण पत्रकारों की चुनौतियों, संसाधनों की सीमाओं और जमीनी रिपोर्टिंग के जोखिमों को विस्तार से रखा। उनकी पत्रकारिता केवल समाचार तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक सरोकार और जनहित को केंद्र में रखकर आगे बढ़ी है। क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय रहते हुए भी राष्ट्रीय मंच पर संवाद स्थापित करने की उनकी पहल, उनके बढ़ते प्रभाव और व्यापक दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। दिल्ली में हुई इस आत्मीय भेंट के दौरान मीडिया की विश्वसनीयता, सामाजिक दायित्व और बदलते डिजिटल परिवेश में पत्रकारिता की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई। 18 फरवरी को श्री चव्हाणके के जन्मदिवस के अवसर पर कैलाश प्रसाद अग्निहोत्री ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएँ दीं और निरंतर सशक्त पत्रकारिता के लिए मंगलकामनाएँ व्यक्त कीं। पत्रकार कल्याण परिषद जिला इकाई बैतूल के पत्रकार साथियों ने इस अवसर पर कहा कि श्री अग्निहोत्री की सक्रियता और संवादशीलता ने यह प्रतीत होता है कि समर्पित पत्रकारिता की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, जहाँ प्रतिबद्धता और दृष्टि हो, वहीं से राष्ट्रीय संवाद की शुरुआत होती है।

मंगल सूत्र लूटने वाला अंतर-राज्यीय गिरोह गिरफ्तार

एक आरोपी को 1300 किमी दूर उड़ीसा के गंजम जिले से,अन्य दो आरोपियों को 500 किमी दूर गुजरात के सूरत से किया गिरफ्तार

देवास। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें चेन स्नैचिंग की एक अंतरराज्यीय गैंग को गिरफ्त में लेकर लाखों का माल बरामद किया है पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोद ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि दिनांक 08.01.2026 को फरियादिया रुकमणी शर्मा निवासी राधागंज द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह अपने पोते को किंडर स्कूल राधागंज, देवास से घर लेकर लौट रही थी तभी मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसके गले से सोने की चेन झपट ली । उक्त घटनाक्रम को त्वरित संज्ञान में लेकर

देवास पुलिस आरोपियों की तलाश में संलग्न हुई, इसी दौरान दिनांक 19.01.2026 को एक अन्य फरियादिया उषा नवरंगे मंदिर जाते समय चेन स्नैचिंग की शिकार हुई । दोनों घटनाओं पर थाना बैंक नोट प्रेस में क्रमशः अपराध क्रमांक 14/2026 एवं 35/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा चेन स्नैचिंग के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक(एल/आर) श्री संजय शर्मा के निर्देशन में तत्कालीन थाना प्रभारी बैंक नोट प्रेस श्री अमित सोलंकी एवं थाना प्रभारी बैंक नोट प्रेस श्रीमति प्रीति कटारे के नेतृत्व में कुल 04 विशेष टीमों का गठन किया गया ।

आपातकाल में हुआ लोकतंत्र का अपहरण, युवाओं को जानना जरूरी : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल। उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि आपातकाल में जिस तरह से लोकतंत्र का अपहरण हुआ, इस विषय में जानने की सबसे ज्यादा जरूरत युवाओं को है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र लंबे समय के संघर्ष के बाद स्थापित हुआ और देश की बेहतरी के लिए हुआ था। देश को फिर से विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाकर दुनिया का नेतृत्व करने के लिए हुआ था, जिससे दुनिया में शांति की स्थापना हो सके और हम लोकतंत्र को अमर बना सकें। उप मुख्यमंत्री शुक्ल गुरुवार को भोपाल में हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी और सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में आयोजित देश में आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 'आपातकाल और युवा' विषय पर केंद्रित राष्ट्रीय विमर्श को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सत्ता के सदुपयोग और दुरुपयोग में क्या अंतर होता है यह हम सभी ने देखा। जब सत्ता का दुरुपयोग होता है तो स्थिति विकट हो सकती है, ये आपातकाल में हम लोगों ने देखा। जनता के आशीर्वाद से मिली हुई सत्ता इस बात के लिए नहीं है कि जो कुर्सी हमारे हाथ से जाने का खतरा आ जाए और वह भी उच्च न्यायालय के आदेश पर, तो हम ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि लाखों लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया जाए, प्रताड़ना दी जाए, प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाए इससे भयावह स्थिति नहीं हो सकती। उन लोगों के लिए इससे बड़ी चिंता का विषय नहीं हो सकता कि लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना एक बड़े मिशन की पूरा करने के लिए गई थी।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब जनसंघ की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक की तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति जिस दिन

मुस्कराकर कह दे कि अब किसी प्रकार की समस्या हमारे सामने नहीं। हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, उस दिन मान जाना कि आपका राजनीति में आने का उद्देश्य पूरा हो गया।

उन्होंने कहा कि एक तरफ यह विचार है और दूसरी तरफ इस प्रकार के विचार हैं कि यदि उच्च न्यायालय ने हमारे खिलाफ निर्वाचन को अवैध कर दिया तो हमने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किए बिना फिर से नया जनादेश प्राप्त करें, उस दिशा में जाने की बजाए अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे और ऐसे असंख्य राजनीति में काम करने वाले वरिष्ठ नेताओं को रात के अंधेरे में पकड़-पकड़कर जेल के अंदर पहुंचाकर जिस तरह से प्रताड़ना दी, इसके बड़ा राजनीतिक अपराध और कुछ नहीं हो सकता और ये आपातकाल के दौरान हुआ। उसके बाद जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हिम्मत न हारते हुए प्रयास जारी रखा ताकि देश गलत दिशा में न जा पाए। उस समय राम बहादुर राय का भी मैं स्मरण करना चाहता हूं, जिनकी जयप्रकाश नारायण के साथ उन योजनाओं को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि किस तरह से आपातकाल की विपरित परिस्थितियों से निपटना है और किस तरह से आगे की कार्ययोजना बनानी है। इसके बाद अंततः इस प्रकार की राजनीति की समाप्ति हुई। जनता पार्टी की सरकार बनी और उस मानसिकता को समाप्त करने का काम हुआ, जिस मानसिकता ने राजनीति को एक परिवार तक सीमित रखने का काम किया। अभी भी उस मानसिकता के लोग उससे उबरे नहीं हैं, अभी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी जो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी में कोई एक भी ऐसा नेतृत्व नहीं तैयार कर सके, जो देश की राजनीति में पार्टी को आगे ले जाने के लिए सामने आए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सौभाग्य है कि भारत आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश बन चुका है। ये युवाओं के लिए संतोष की बात है, क्योंकि आगे उनका लम्बा भविष्य है, लेकिन आर्थिक महाशक्ति बनने के साथ-साथ हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और इसी लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विरासत से विकास। हम अपना एक पैर जमीन में जमाकर और लम्बी छलांग लगाने की दिशा में देश को आगे ले जाने का काम होना चाहिए, जिससे विकास हमारे लिए अभिशाप न बने, बल्कि वरदान बने। इसलिए आपातकाल के जो कठिन दौर रहे हैं, सारे युवाओं को उसको पढ़ना चाहिए। युवा जो देश को आगे ले जाने का काम करेंगे, उन्हें पीछे की ओर सिंहावलोकन करने की आवश्यकता है।

विधानसभा में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा के यहां लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई में 41 करोड़ की संपत्ति का खुलासा

भोपाल। कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह द्वारा मार्च 2025 में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दिनांक 18 फरवरी 2026 को प्रस्तुत जानकारी में की कार्रवाई से जुड़े अत्यंत गंभीर और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी के निवास एवं कार्यालय पर 19 दिसंबर 2024 को लोकायुक्त की संयुक्त टीमों द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 9 सदस्यीय टीम ने निवास और 7 सदस्यीय टीम ने कार्यालय की तलाशी ली। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में चल एवं अचल संपत्ति का खुलासा हुआ, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 41 करोड़ रुपये बताई गई है।

जप्त संपत्ति का विवरण इस प्रकार है

(अ) नकद, सोना, चांदी / चल संपत्ति

ज़नकद राशि -2,83,23,000

स्वर्ण आभूषण

- वजन : 558.64 ग्राम
- डायमंड : 10.80 कैरेट
- कीमत : 50,37,425

चांदी

- वजन : 233.936 किलोग्राम
- कीमत : 2,10,50,716

(ब) अन्य वस्तुएं एवं वाहन (इंट्री)

अनुमानित कीमत : 2,54,73,481

(स) अचल संपत्ति (दस्तावेज़ अनुसार)

अनुमानित कीमत - 30,00,00,000

(द) बैंक एफ.डी. राशि : 3,08,46,158

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि एक आरटीओ आरक्षक के पास आय से कई गुना अधिक संपत्ति पाई गई, जो गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की आशंका को दर्शाती है। इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिसंबर 2024 में जब्त की गई संपत्ति की वर्तमान बाजार कीमत अब लगभग दोगुनी हो चुकी है। उनके अनुसार यह केवल अवैध संपत्ति का मामला नहीं, बल्कि सत्ता संरक्षण में पनपे संगठित भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कुछ मंत्रियों की इस पूरे प्रकरण में मिलीभगत रही है, जिसके कारण मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को लगभग एक वर्ष तक दबाकर रखा गया।

जयवर्धन सिंह कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित तथ्य सार्वजनिक होने में हुई देरी से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सत्ता में बैठे लोग भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। उनके अनुसार प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे की लूट सुनियोजित तरीके से की जा रही है और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया गया। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय और पारदर्शी जांच कर जिम्मेदार व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए तथा जनता के साथ हुए विश्वासघात के लिए जवाबदेही तय की जाए। यह मामला प्रदेश में प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। विधानसभा में प्रस्तुत जानकारी के बाद यह आवश्यक हो गया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष, गहन और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए तथा दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो।

मांगें

1. प्रकरण की विस्तृत जांच कर संपूर्ण संपत्ति का स्रोत सार्वजनिक किया जाए।
2. दोष सिद्ध होने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
3. इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सख्त निगरानी तंत्र लागू किया जाए।

प्रदेश की जनता पारदर्शी शासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की अपेक्षा रखती है। इस दिशा में ठोस कार्रवाई समय की मांग है।

इस संबंध में मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत- उक्त गंभीर प्रकरण को देखते हुए इस संबंध में स्वयं मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत प्रस्तुत कर संपूर्ण मामले की उच्चस्तरीय जांच एवं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी, ताकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया जा सके तथा जनता का शासन व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे।

संक्षिप्त समाचार

महिलाओं का यौन अधिनियम उत्पीड़न अधिनियम विषय पर कार्यशाला आयोजित

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें सभी जिला अधिकारियों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत कार्यालयों में समितिसां गठित किए जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय तथा जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश जैन ने अधिनियम के तहत समिति गठित किए जाने, समिति के सदस्यों का चयन, शिकायत प्राप्त होने पर की जाने कार्यवाही की प्रक्रिया सहित अधिनियम के संबंध में जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की भी जानकारी दी गई। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स प्रार्थना मिश्रा द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओ का लैंगिक उत्पीडन अधिनियम (रोकथाम,निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के संबंध में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। शाखा प्रभारी शिवानी राजपूत द्वारा शी बॉक्स पोर्टल के संबंध में जानकारी प्रदान की गई एवं सभी विभाग अधिकारियों को पोर्टल पर जानकारी अधतन करने के संबंध में बताया गया।

धरती आबा अभियान अंतर्गत सत्ताखेड़ी जाजौन में शिविर आयोजित

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले के अंतर्गत चिह्नित सहरिया जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु धरती आबा अभियान के तहत ग्राम सत्ताखेड़ी जाजौन में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। आयोजित शिविर में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं एवं आवेदनों को प्राप्त कर उनके निराकरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई। शिविर में ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, पात्रता पर्ची, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसान कल्याण योजनाओं एवं अन्य योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। पात्र हितग्राहियों के आवेदन मौके पर ही भरवाए गए तथा आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन भी किया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान करते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविरों का मुख्य उद्देश्य योजनाओं को गांव स्तर तक पहुंचाना एवं पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करना है। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी समस्याएं एवं आवेदन प्रस्तुत किए।

नगद इनाम की घोषणा

विदिशा (निप्र)। पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी के द्वारा थाना सिविल लाइन विदिशा में दर्ज अपराध क्रमांक 745/2025 की विभिन्न धाराओ के फरार आरोपीगण सोहन पुत्र मोहन मोगिया (पारदी), जैकी पुत्र गौतम मोगिया (पारदी), उवेश उर्फ उमेश पुत्र स्व रमन मोगिया (पारदी) निवासीगण ग्राम गुलगांव थाना सांची जिला रायसेन (म0प्र0) की सूचना देने वालो को दो-दो हजार रूपए (प्रत्येक पर) नगद राशि देने की उद्घोषणा की है। सूचनाकर्ता चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

बेहड़ी ढाना के आंगनवाड़ी में कुष्ठ विकृति एवं बचाव शिविर का आयोजन

बैतूल (निप्र)। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत घोड़ाडोंगरी विकासखंड के ग्राम बेहड़ीढाना आंगनवाड़ी क्रमांक-3 में कुष्ठ विकृति एवं बचाव शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि शिविर में 12 मरीजो को एमसीआर माइक्रो सेल्यूलर रबर जूते और सैंडल का वितरण किया गया।कुष्ठ मरीजों को अपनी दिनचर्या में सावधानी बरतने की समझाइश दी गई एवं विकृति से बचाने के लिए कृत्रिम पसीना बनाने की विधि बताई गई और हाथ-पैरों को सुरक्षित रखने, देखभाल करना सिखाया गया। इसके अलावा प्रभावित स्थान को चोट से बचाने की सलाह भी दी गई। साथ ही बताया कि नहाते समय गर्म पानी का उपयोग न करें, चाय के कप को गमछे से या अन्य किसी कपड़े से पड़कर ही चाय पिए, खाना बनाते समय शंसी का उपयोग करें, नंगे पैर ना चले, एक बार दवाई चालू करने के उपरांत इसे लगातार एक वर्ष तक खाएं। शिविर में उपस्थित मरीजों को जल तेल उपचार करने की शपथ दिलाई गई। शिविर में विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक ईश्वर मंडलेकर, एनएमए श्री राजेश मेहतो, श्री लिखीराम सागरे, सरोज भोसले, एएनएम लता भोरसे, संगीता भोरवंशी, कंचन पाण्डे, नरेन्द्र भोरसे उपस्थित रहे।

कुबेरेश्वर धाम में व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखने के निर्देश ड्यूटी को सेवा भाव से निभाएं : कलेक्टर-एसपी

कलेक्टर एसपी ने कुबेरेश्वर धाम का जायजा लिया प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित वातावरण मिले तथा वे श्रद्धा और आस्था के साथ पूजन और कथा का श्रवण कर सकें- कलेक्टर

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के एवं एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला ने कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा महोत्सव के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन एवं समिति द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होने तैनात सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे अपनी ड्यूटी पूरी गंभीरता, सजगता और जिम्मेदारी के साथ निभाएं।

उन्होंने कहा कि धाम में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी का व्यवहार सहयोगात्मक और सेवा भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल शासकीय ड्यूटी नहीं, बल्कि सेवा का अवसर है, जिसे पूरी निष्ठा से निभाया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने-अपने निर्धारित ड्यूटी क्षेत्र में पूरे समय उपस्थित रहें तथा बिना अनुमति ड्यूटी स्थल न छोड़ें।

श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वे सतर्क एवं सक्रिय रहें। उन्होंने कहा कि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन, जानकारी एवं आवश्यक सहयोग तत्काल उपलब्ध कराया जाए। पेयजल व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि धाम परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। पानी के टैंकर, टंकियां एवं पाइप लाइन की नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि कहीं भी कमी की स्थिति उत्पन्न न हो। पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग सुनिश्चित की जाए तथा मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति न बनने दी जाए।

यातायात पुलिस एवं अन्य तैनात कर्मी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सरल आवागमन में सहयोग करें, ताकि वे बिना किसी कठिनाई के धाम पहुंचे और वापस जा सकें। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अस्पताल में सभी आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस सेवाएं तत्पर रहें तथा किसी भी मरीज को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाए।

कंट्रोल रूम एवं हेल्प डेस्क की व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि यहां चैबीसों घंटे अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहें। श्रद्धालुओं द्वारा की गई हर शिकायत, समस्या या जानकारी संबंधी अनुरोध का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि हेल्प डेस्क श्रद्धालुओं के लिए सहायता का प्रमुख केंद्र है, इसलिए यहां कार्यरत कर्मचारी संवेदनशीलता एवं विनम्रता के साथ कार्य करें। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाए रखते हुए व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कुबेरेश्वर धाम आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित वातावरण मिले तथा वे श्रद्धा और आस्था के साथ दर्शन एवं कथा का श्रवण संपन्न कर सकें। निरीक्षण के दौरान एएसपी श्रीमती सुनीता रावत तथा एसडीएम श्री तनमन्य वर्मा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।

नर्मदापुरम में स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया काम

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिला अस्पताल में सोमवार को स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर काम किया। वेतन विसंगति और नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। मांगें पूरी नहीं होने पर संगठन ने अब 24 फरवरी को भोपाल में 'न्याय यात्रा' निकालने की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह मीना ने बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों की वर्षों से लंबित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर महासंघ द्वारा कई बार शासन-विभाग को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। महासंघ ने निर्णय लिया है कि अगर समय सीमा में मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है, तो प्रदेश व्यापी आंदोलन जारी रहेगा। जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी, कर्मचारी मानव सेवा करते हैं, यह महत्त्वपूर्ण विभाग है। मुख्यमंत्री से आग्रह है कि समय रहते मांगों पर विचार कर शीघ्र निराकरण करें। 24 फरवरी को हजारों की संख्या में भोपाल एकत्रित होकर न्याय यात्रा रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। इसके बाद हड़ताल पर जाएंगे।

ये हैं प्रमुख मांगें

चिकित्सकों की तरह रात्रिकालीन आकस्मिक चिकित्सा भत्ता दिया जाए। रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, अटेंडेंट को रेडिएशन जोखिम भत्ता मिले। ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज की तरह समस्त मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग ऑफिसर को तीन एवं चार वेतन वृद्धि दी जाए। अन्य राज्यों की तरह सभी कैडरों के पदनाम बदले जाएं। सामान्य प्रशासन विभाग की 2023 की नीति एनएचएम में संविदा कर्मचारियों के लिए पूर्ण रूप से लागू हो या नियमित किया जाए। एड्स नियंत्रण समिति के संविदा कर्मचारियों को एनएचएम विभाग में मर्ज किया जाए अथवा नियमित करें। आउटसोर्स एवं रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बने, ताकि समय पर वेतन और सेवाएं सुरक्षित रहें।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत विद्यार्थियों को दी बाल विवाह के दुष्प्रभावों की जानकारी

हरदा (निप्र)। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 2026 के अंतर्गत हरदा जिले के पिनेकल स्कूल हरदा एवं ज्ञान गंगा हाई स्कूल हरदा में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राजा रंगारे जी के नेतृत्व में बालक बालिकाओं को बाल विवाह के दुष्प्रभावों व गुड टच बेड टच की जानकारी दी गई। इस दौरान चाइल्ड लाइन से सुश्री दिव्या राजपूत ने विद्यार्थियों को गुड टच एवं बेड टच के बारे में समझाया। उन्होने इस दौरान बताया कि यदि बालक की उम्र 21 तथा बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम है और बालक या बालिका का विवाह हो रहा हो तो वह बाल विवाह कहलाता है। उन्होने बताया कि बाल विवाह से बाल विवाह करने वाले बालक व बालिका की शिक्षा रुक जाती है, घरेलू हिंसा के मामले बढ़ जाते है, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ खराब होता है तथा जीवन जीने के अवसर कम हों जाते है। साथ ही उन्हें ऐसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाइल्ड लाइन से श्री शुभम् धार्मिक ने बताया कि बालश्रम बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे शिक्षा का अधिकार छिन जाता है। वे कुपोषण और गंभीर बीमारियों का शिकार बनते हैं तथा खतरनाक स्थितियों में काम करने के कारण शारीरिक शोषण व मृत्यु का खतरा रहता है। यह गरीबी के दुष्कर्म को बढ़ाता है और बचपन का हनन करता है। इस दौरान रविराज राजपूत ने बच्चों को बताया कि चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 चाइल्ड लाइन का टोल-फ्री, आपातकालीन फोन नंबर है, जो भारत में मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद के लिए चौबीस घंटे काम करता है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है, जिसे कोई भी बच्चा या अन्य व्यक्ति आपातकालीन सहायता जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, या शोषण के लिए डायल कर सकता है। उन्होने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य संकट में फंसे बच्चों को तुरंत सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना है। इसमें मेडिकल, आश्रय, कानूनी सहायता और भावनात्मक मार्गदर्शन शामिल हो सकता है। कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग से श्रर आशीष जोशी एवं स्कूल डायरेक्टर श्री अब्दुल सईद, प्राचार्य श्रीमती प्रियंका तोमर, श्री अर्जुनसिंह चौहान सहित स्कूल स्टाफ उपस्थित रहे।

जेएच कॉलेज की मेजबानी में चल रहे महिला एवं पुरुष राज्य स्तरीय अंतर विश्वविद्यालयीन पिट्ठू प्रतियोगिता का समापन

जबलपुर ने पहना महिला स्टेट चैंपियन का ताज, पुरुष वर्ग में इंदौर बना विजेता

बैतूल (निप्र)। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जेएच कॉलेज की मेजबानी में चल रही महिला एवं पुरुष राज्य स्तरीय अंतर विश्वविद्यालयीन पिट्ठू प्रतियोगिता का समापन मुख्य अतिथि श्री आदित्य शुक्ला के आतिथ्य तथा विशिष्ट अतिथि श्री अतीत पवार व विकास प्रधान की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर श्री अदित्या शुक्ला ने दोनों विजेता टीमों को बधाई देते हुए कहा कि पिट्ठू जैसे पारंपरिक खेल में खिलाड़ियों का उत्कृष्ट तकनीकी कौशल देखने को मिला। विशिष्ट अतिथि श्री अतीत पवार और विकास प्रधान ने भी सभी विजेता टीमों को बधाई देते हुए सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। प्राचार्य डॉ मीनाक्षी चौबे ने सभी खिलाड़ियों के खेल की प्रशंसा करते हुए महिला और पुरुष वर्ग की विजेता टीमों को बधाई दी। समापन समारोह के अंत में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सिवनी के डॉ. के सी राउर ने महिला एवं पुरुष राज्य स्तरीय अंतरविश्वविद्यालयीन पिट्ठू प्रतियोगिता के आयोजन का प्रतिवेदन पढ़ा। समापन समारोह का आभार वक्तव्य क्रीड़ा अधिकारी डॉ. नीलिमा पीटर द्वारा दिया गया।

सेमी फाइनल और फाइनल मैच

महिला वर्ग के रोमांचक पहले सेमीफाइनल में इंदौर ने छिंदवाड़ा को शिकस्त देते हुए फाइनल में प्रवेश किया, तो दूसरे सेमीफाइनल में जबलपुर ने सागर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इंदौर और जबलपुर के बीच हुए रोमांचक फाइनल मुक़ाबले में जबलपुर ने इंदौर को हरा कर महिला राज्य स्तरीय अंतर विश्वविद्यालयीन पिट्ठू प्रतियोगिता में विजेता का ताज पहना, तो इंदौर की टीम महिला उप विजेता बनी। इसके अलावा पुरुष वर्ग में पहला सेमीफाइनल में इंदौर और भोपाल के बीच हुआ, जिसमे इंदौर ने भोपाल को हरा कर फाइनल की ओर कदम बढ़ाया, वही दूसरे सेमी फाइनल में जबलपुर ने उज्जैन को शिकस्त देते हुए फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मैच में इंदौर और जबलपुर के बीच अत्यंत रोमांचक मैच देखने को मिला। फाइनल में इंदौर ने जबलपुर के पुरुष वर्ग का भी चैम्पियन बनने के सपनों पर पानी फेरते हुए विजेता का ताज पहना।

घर-घर डेटा संग्रहण के लिए अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में जनगणना 2027 की आवश्यक जानकारी से जिला एवं चार्ज स्तर के अधिकारियों हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को भारत की जनगणना के संबंध में संक्षिप्त परिचय एवं नीति निर्माण सहित जनगणना 2027 के मुख्य बिंदुओं एवं प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया। प्रशिक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा सभा कक्ष में उपस्थित जिले के समस्त अनुविभागीय जनगणना अधिकारी, चार्ज जनगणना अधिकारी (तहसीलदार), (मुख्य नगरपालिका अधिकारी) चार्ज जनगणना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी को प्रक्रिया में आंकड़ों की सटीकता के महत्व आदि की जानकारी से विस्तार पूर्वक प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जनगणना 2027 के दौरान डेटा संग्रह और उसके जांच की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि आंकड़ा संग्रहण करने के लिए प्रगणक द्वारा घर-घर जाकर स्वयं के मोबाइल फोन में एप के माध्यम से जानकारी एकत्रित करना तथा स्वगणना (एसई) पोर्टल के माध्यम से जानकारी का एकत्रीकरण किए जाने के संबंध में भी अवगत कराया गया। स्वगणना पोर्टल के माध्यम से नागरिक जानकारी अपडेट कर सकेंगे जिसे बाद में प्रगणक द्वारा सत्यापित कर सबमिट किया जाएगा। इसी प्रकार प्रशिक्षण के दौरान जनगणना संभाग प्रभारी श्रीमती अनामिका जैन एवं जिला प्रभारी सुश्री आयुषी द्वारा उपस्थित अधिकारियों को प्रगणक और पर्यवेक्षक के कार्य प्रवाह के संबंध में भी विस्तार पूर्वक समझाया गया। उन्होंने बताया कि पूरी जनगणना प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षण, एचएलबी की पहचान तथा लेआउट मैप, डाटा संग्रहण एवं सत्यापन, डाटा सिंक एवं पर्यवेक्षण तथा समापन और प्रमाणन प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

बैठक के दौरान प्रगणकों के मुख्य कर्तव्य से भी उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया जिसमें प्रशिक्षण, मोबाइल एप के उपयोग, मकान सूचीकरण, एचएलबी का लेआउट तैयार करना, एचएलओ एप के माध्यम से डाटा एकत्रित करना सहित पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने जैसे घटकों की जानकारी दी गई। इसी प्रकार पर्यवेक्षकों के मुख्य कर्तव्य से अवगत कराते हुए बताया गया कि सुपरवाइजर ऐप और फील्ड निरीक्षण के माध्यम से प्रगणक के डेटा की निगरानी,फील्ड कार्य के दौरान प्रगणक को इस कार्य से सम्बंधित कोई समस्या आए तो उसका निराकरण जैसी अन्य जानकारी भी प्रदाय की गई।

प्रशिक्षण के दौरान एडीएम श्री राजीव रंजन पांडे, अपर कलेक्टर श्री अनिल जैन, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती नीता कोरी सहित समस्त अनुविभागीय जनगणना अधिकारी, चार्ज जनगणना अधिकारी (तहसीलदार), (मुख्य नगरपालिका अधिकारी) चार्ज जनगणना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।

भोजपुर में लोकधारा और काव्यधारा का संगम, 'महादेव' महोत्सव ने बिखेरी सांस्कृतिक आभा

भोजपुर मंदिर परिसर में आयोजित तीन दिवसीय महादेव भोजपुर महोत्सव का समापन

रायसेन (निप्र)। भोजपुर में लोकधारा और काव्यधारा का संगम, 'महादेव' महोत्सव ने बिखेरी सांस्कृतिक आभा भोजपुर मंदिर परिसर में आयोजित तीन दिवसीय महादेव भोजपुर महोत्सव का समापन रायसेन, 17 फरवरी 2026 मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन, रायसेन के सहयोग से ऐतिहासिक एवं प्राचीन स्थल भोजपुर के मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय ''महादेव'' भोजपुर महोत्सव का मंगलवार को समापन हो गया। महोत्सव के अंतिम दिन लोक गीत एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। भोजपुर की सांस्कृतिक संध्या उस समय विशेष आभा से आलोकित हो उठी, जब एक ओर लोकगायन की स्वर लहरियों ने परम्पराओं की सोंधी महक बिखेरी, दूसरी ओर काव्य की ओजस्वी अभिव्यक्तियों ने वातावरण को 9 रसों से परिपूर्ण बना दिया। भोपाल के श्री बलराम पुरोहित ने मधुर वाणी से लोकजीवन के सौंदर्यपूर्ण परिदृश्य को जीवंत कर दिया। वहीं, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में दिल्ली के श्री अशोक चक्रधर, मुंबई के श्री दिनेश बावरा, आगरा के श्री प्रताप फौजदार, दिल्ली के श्री गजेन्द्र सोलंकी, आगरा की सुश्री रुचि चतुर्वेदी, मथुरा की सुश्री पूनम वर्मा एवं दिल्ली की सुश्री मनु वैशाली ने अपनी सशक्त एवं विविध संवेदनाओं से सजी रचनाओं के माध्यम से काव्यधारा का इस अनुपम संगम को साहित्यिक वैभव से आलोकित कर एक अविस्मरणीय उत्सव में रूपांतरित कर दिया। अंतिम दिवस की पहली प्रस्तुति श्री बलराम पुरोहित की हुई। उन्होंने सरस्वती वंदना के माध्यम से कंठ में विराजमान माँ शारदा को नमन कर वातावरण को भक्तिरस से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात हम जाने कछु नोने से हुईयै राजा हिमांचल के दामाद..., भोला हो कै तैयार करके सोलह श्रृंगार..., शिव कैलाश पति के..., बनवा बनवी महादेव जी..., राजा भोज के भोज नगर में बैठे भोलानाथ... तथा सिर बांधे मुकुट खेले होरी... जैसे लोकगीतों की सुमधुर प्रस्तुति से श्रोताओं को लोकसंस्कृति से अवगत कराया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में श्री अशोक चक्रधर ने अपनी विशिष्ट शैली में इस दिल की धड़कन में हम दोनों की साझेदारी है, आधी सांस हमारी इसमें आधी सांस तुम्हारी है... प्रस्तुति से प्रेम, संवेदना और आत्मीयता को व्यक्त किया। इसके पश्चात आंधी हो तूफां हो चाहे भीषण सर्दी गर्मी हो..., सबने हिम्मत हारी, तुमने कभी न हिम्मत हारी है...., जन-जन का सम्मान, तुम्हारी वर्दी पर बलिहारी है... के माध्यम से सेना के प्रति सम्मान और उसके साहस को अभिव्यक्त किया। श्री दिनेश बावरा ने पहले नदी, फिर तालाब, फिर कुआँ, फिर हैंडपंप, फिर नल की टोटी... और अब पानी की बोतल, हमने पानी को सिमटने का सफ़र देखा... रचना के माध्यम से पानी बचाने का संदेश दिया। अगली रचना इस दुनिया को खतरा ना चीन से है, ना पाकिस्तान से, ना अमेरिका से, ना इज़राइल से, इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा, आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है... से मोबाइल से मानव शरीर पर हो रहे प्रभाव और आपसी संबंध में पनप रहे तनाव को उजागर किया। श्री प्रताप फौजदार ने वफ़ा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है... और खरगोशों के हाथ में डम्बल, पहली बार ही देखा है, और दर्प का टूटा संबल, पहली बार ही देखा है... रचना से समकालीन संवेदनाओं को स्वर दिया। अगली कड़ी में श्री गजेन्द्र सोलंकी ने नए युग की कहानी का नया उल्लास लिखना है, दिलों की धड़कनों पे प्यार का अहसास लिखना है, बदलते वक्त की आहट सुनी तो साँस यूं बोली, हमें भारत की धरती पर सुखद मधुमास लिखना है... रचना से राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। कार्यक्रम को विस्तार देते हुए सुश्री रुचि चतुर्वेदी ने लाल महावर लगे मेरे इन पाँव की चिंता मत करना, सीमा पर जागे रहना तुम गाँव की चिंता मत करना...., पुण्य चरणों की रज हो गया, भावनाओं का ध्वज हो गया, राधिका कृष्ण इक हो गए, प्रेम का नाम ब्रज हो गया..., डूबकर जिनमें खुद को पाया है, उन्हीं आंखों को गुनगुनाया है... और शिव शिवशंभू शिव भूतनाथ शिव प्रलयंकर गल धरें नाग, नटराज वही गिरिजापति हैं, डम डम डमरू करता निनाद... जैसी भगवान शिव और श्रीकृष्ण भक्ति से ओत-प्रोत रचनाओं का पाठ किया।

राइट क्लिक

अब बांग्लादेश में भी 'जनादेश चोरी' के आरोप के क्या मायने?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

चुनाव हारने के बाद 'जनादेश चोरी' अथवा 'वोट चोरी' का इल्जाम लगाना अब अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृति बनती जा रही है। पहले इस तरह के आरोप अमूमन हारने वाली सियासी पार्टियां चुनाव में धांधली अथवा नतीजों में हेराफेरी के रूप में लगाती थीं और ये आरोप अक्सर उस पार्टी पर लगते थे, जो चुनाव के समय सत्ता में रहती थी। भारत में भी राहुल गांधी और कुछ विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ भाजपा और मोदी सरकार पर 'वोट चोरी' और 'जनादेश चुराने' के आरोप लगातार लगाते रहे हैं। अब बांग्लादेश में भी इसकी अनगूंज सुनाई दे रही है। वहां चुनाव में मात खाने वाली जमात-ए-इस्लामी और 11 पार्टियों के गठबंधन ने सत्ता में आई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) पर 'जनादेश चुराने' और वोटों की गिनती में 'हेराफेरी' का आरोप लगाया है। नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सोशल मीडिया में ट्रोलकर उन्हें चुनाव जितवाने वाला 'इंजीनियर' बताया जा रहा है। हार की हताशा में ऐसा ही आरोप छह साल पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने भी लगाया था, जब राष्ट्रपति पद का दूसरा चुनाव वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों हार गए थे। दरअसल इस बात की पड़ताल दिलचस्प है कि ऐसे आरोप महज हार की बौखलाहट में लगाए जाते हैं? अपनी कमियों को छुपाने के लिए लगाए जाते हैं अथवा इनमें सच में बहुत दम होता है? खासकर तब, जब जीत- हार तगड़े मार्जिन के साथ हुई हो? या फिर ऐसे आरोपों का वास्तविक मकसद जनादेश को नकारकर उसका अपमान करना है?

ऐसा लगता है कि देश कोई-सा भी हो, अगर लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होने हैं तो किसी न किसी की हार या जीत तो होगी ही। यानी जनता जो आदेश देगी, वही वैध और शिरोधार्य होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से जनादेश की पवित्रता पर संदेह का दाग लगाने की संस्कृति तेजी से फली-फूली है। इसमें आंशिक सच्चाई भी है। बांग्लादेश के ताजा आम चुनाव वहां की मोहम्मद युनूस अंतरिम सरकार की देखरेख और प्रशासन की निगरानी में हुए थे। बीएनपी तो सत्ता से बाहर ही थी। बल्कि युनूस सरकार परोक्ष रूप से मुस्लिम कट्टरपंथी जमात- ए- इस्लामी और जेन-जी की नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के दबाव में काम कर रही थी। कोशिश थी कि बांग्लादेश को उदार इस्लामिक स्टेट से कट्टरपंथी इस्लामिक देश में तब्दील कर कड़े शरिया कानून लागू किए जाएं। यानी देश में बंगाली अस्मिता की जगह मुस्लिम पहचान को तरजीह दी जाए। लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने इस चाल को साफ नकार दिया, जिसमें वहां की महिलाओं की विशेष भूमिका रही, जो बुर्के में जिंदगी गुजारने के लिए कतई तैयार नहीं थी। जमात इस भावना को समझना नहीं चाहती थी। नतीजा यह हुआ कि अपेक्षाकृत मध्यमार्गी बीएनपी को चुनाव में बंपर जीत मिली। उसने 299 में 209 सीटें और 49.97 फीसदी यानी आधे वोट हासिल किए, जबकि कट्टर इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी और 11 पार्टियों के गठबंधन को 68 सीटें और 31.76 प्रतिशत वोट ही मिले। शेख हसीना की सरकार को हटाकर 'नया बांग्लादेश' बनाने का दावा करने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी को महज 6 सीटें और 3 फीसदी वोट ही मिले। उसके ज्यादातर प्रत्याशी चुनाव हार गए।

इस तगड़ी हार के बाद जमात और एनसीपी आरोप लगा रहे हैं कि चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। यानी माहौल तो हमारे पक्ष में था, लेकिन नतीजे विपरीत आए। मतदान ठीक हुआ, लेकिन मतगणना में हेराफेरी हुई। हमारे कई प्रत्याशियों को मामूली अंतर से हरवा दिया गया इत्यादि। ये सभी आरोप भारत में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा चुनाव नतीजों के बाद मोदी सरकार और भाजपा पर लगाए जाने वाले आरोपों की फोटो कॉपी लगाते हैं। यहां एक फर्क और है। बांग्लादेश में मतदान बैलेट पेपर से हुआ था, जबकि भारत में ईवीएम से चुनाव होता है। कांग्रेस और विपक्ष यह आशंका बार-बार जाहिर करते रहे हैं कि चुनाव आयोग की मदद से भाजपा ईवीएम में गड़बड़ी कराती है और चुनाव जीत जाती है। लेकिन बांग्लादेश का उदाहरण बताता है कि अगर जमात और अन्य पार्टियों के आरोप सही हैं तो बैलेट पेपर में धांधली तो और भी आसान है। यह हमने पाकिस्तान के आम चुनाव में देखा, जहां बैलेट पेपर के जरिए हुए मतदान में वहां की सेना ने खुलेआम धांधली की और शहबाज शरीफ को जितवा दिया। अमेरिका में बैलेट पेपर और मशीन दोनों के जरिए चुनाव होता है, फिर भी ट्रंप सत्ता में रहकर भी पिछला चुनाव हार गए थे। भारत में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां 'वोट चोरी' का आरोप अमूमन उन राज्यों में लगाती है, जहां भाजपा सत्ता में है। लेकिन बांग्लादेश में तो चुनाव जीती बीएनपी सत्ता से बरसों से बाहर थी, फिर वो इतने बड़े पैमाने पर 'गड़बड़ी' करने में कैसे कामयाब हो गई? और जमात जैसी पार्टियां, जिनका कि सत्ता पर परोक्ष नियंत्रण था, इस 'गड़बड़ी' को क्यों नहीं रोक पाई? उसका यह दावा कि चुनाव के समय माहौल उनके 'पक्ष' में था तो मतदान के वक्त अरब सागर की हवा कैसे बदल गई?

हाल में भारत के राज्य तेलंगाना में स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव हुए हैं। इसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस को बंपर जीत मिली है। ये चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए गए। इन नतीजों से कांग्रेस 'संतुष्ट' है, क्योंकि उसे जीत मिली है, जबकि चुनाव नतीजों पर विपक्षी भाजपा ने सवाल उठाया अब कोई 'जनादेश चुराने' का आरोप क्यों नहीं लगा रहा है? इसका सीधा मतलब है कि यदि नतीजा अपने पक्ष में आए तो सब ठीक और न आए तो 'आंगन टेढ़ा।'

अब सवाल यह है कि भारत में ईवीएम से जहां चुनाव होते हैं, वहां कांग्रेस अमूमन हार जाती है और जहां बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो जीत जाती है? यह मतदान के माध्यम और तरीके का नतीजा है अथवा जनमत की अभिव्यक्ति? अगर ईवीएम से ही हार-जीत तय होती तो भाजपा को दक्षिणी राज्यों और बंगाल में भी भारी बहुमत से जीतना चाहिए था। क्योंकि विपक्ष के अनुसार उसके पास तो चुनाव आयोग का रिमोट कंट्रोल भी है। और अगर बैलेट पेपर से ही हार-जीत का उचित फैसला होता हो तो बांग्लादेश में जमात और एनसीपी को बंपर जीत मिलनी चाहिए थी।

कहने का आशय यह कि जब राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर पर अपना असर नहीं छोड़ पातीं, लोगों से जुड़ने का कैडर उनके पास नहीं होता, चुनाव जीतने की जिद नहीं होती, जनमानस से पार्टियों की सोच का तालमेल नहीं बैठता या फिर वे केवल हवा में लठ घुमा कर और शाब्दिक क्रांति से ही चुनाव जीतना चाहती हैं तो यह केवल खुद को धोखे में रखना है। चुनाव जीतने के लिए सत्ता और धन के दुरूपयोग के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जनता की नब्ज को पकड़ना है। बांग्लादेश में भी जमात द्वारा लगाया जा रहा 'जनादेश चोरी' का आरोप तब सही माना जा सकता था, जब दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के बीच? हार-जीत का फैसला मामूली अंतर से होता। अब कोई जनता की सोच और समझ पर ही प्रश्न चिन्ह लगाना चाहे तो लोकतंत्र में उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता।

मप्र बजट का सत्र

भागीरथपुरा कांड पर विपक्ष का हंगामा

● डिप्टी सीएम शुक्ला और मंत्री विजयवर्गीय का इस्तीफा मांगा, अनूपपुर में फीस के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठा

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है। कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बजट को आम जनता के लिए निराशाजनक बताते हुए इसे 'ख्याली पुलाव' करार दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। हंगामे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अगले प्रश्न के लिए कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती का नाम पुकारा, लेकिन शोर-शराबे के कारण वे सवाल नहीं रख सके। इसके बाद फुंदेलाल मार्को को बुलाया गया, मगर हंगामा जारी रहा। स्थिति न संभलने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी। इस बीच कांग्रेस विधायक गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करते रहे। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर की घटना को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताते हुए संबंधित मंत्री (मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, इंदौर सांसद शंकर लालवानी और इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव) के इस्तीफे की मांग की।

भागीरथपुरा मौत कांड पर विपक्ष का हंगामा

इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के मुद्दे पर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्रियों के इस्तीफे की मांग उठाई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए ऐसी चर्चा से न्यायालय की अवमानना की स्थिति बन सकती है। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने सुझाव दिया कि सदन में बहस के बजाय संबंधित मंत्री से अलग बैठक कर चर्चा करना बेहतर होगा। पूर्व अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने भी कहा कि अदालत में मामला होने से सदन में चर्चा उचित नहीं। जवाब में डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि 21 से 29 दिसंबर के बीच डायरिया फैलने के बाद स्थिति गंभीर हुई और 22 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की राहत दी गई। इस पर सिंघार ने मृतकों की संख्या 35 बताते हुए सभी को मुआवजा देने और मंत्रियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और एक आईएएस अधिकारी को निलंबित भी किया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के राहत कार्यों का भी उल्लेख किया गया।

12वीं टॉपर ने माता-पिता, भाई को मार डाला

● बैतूल में भांजे की भी हत्या की कोशिश, मर्डर के बाद शवों के पास बैठा रहा आरोपी

बैतूल (नप्र)। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में बेटे ने अपने मां-बाप और भाई को मार डाला। पांच साल के भांजे को भी मारने की कोशिश की। मर्डर के बाद दरवाजा बंद कर लाशों के पास बैठा रहा। फर्श और दीवारों पर खून के कतरे बिखरे मिले हैं। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान पिता राजू उर्फ हंसू धुर्वे (55), मां कमलती धुर्वे (40) और भाई दिलीप धुर्वे (40) के रूप में हुई है। तीनों सांवगा गांव के रहने वाले थे। वहीं 5 वर्षीय भांजे प्रशांत परते की हालत गंभीर बताई जा रही है।

दरवाजा बंद था, शवों के पास बैठा था आरोपी

पड़ोसियों के मुताबिक गुरुवार दोपहर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो अनहोनी का शक हुआ। पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। जब ग्रामीण दरवाजा तोड़कर घर के अंदर गए, तो आरोपी दीपक धुर्वे घटनास्थल पर ही मौजूद था। इस दौरान वह तीनों शवों के पास चुपचाप बैठा मिला। मौके पर एक बिल्ली का शव भी मिला है। आशंका है कि बिल्ली को भी मार दिया है। वारदात की जानकारी पड़ोसियों ने फौरन कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची।

मानसिक संतुलन पिछले 4-5 साल से ठीक नहीं था

पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि दीपक का मानसिक संतुलन पिछले 4-5 साल से ठीक नहीं था। वह हाल ही में नागपुर से इलाज कराकर लौटा था। वह परिवार में सबसे बड़ा है। सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा भी दी थी।

सीआरपीएफ में सिलेक्शन नहीं होने से मेंटली डिस्टर्ब था

आरोपी की बहन शांता ने बताया कि आरोपी दीपक बड़ा भाई है। वह कुछ नहीं करता था। उसका दिमाग खराब है। दीपक ने 12वीं क्लास में टॉप किया था, लेकिन सीआरपीएफ में सिलेक्शन नहीं होने की वजह से वह मेंटली अनस्टेबल हो गया था। कोतवाली पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हत्या की जगह से लोहे की रॉड और डंडे मिले हैं। पुलिस ने लोहे की रॉड और डंडे जब्त कर लिए हैं। वहीं फोरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। मामले की जांच जारी है।

महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प

बैरिकेडिंग पर चढ़ीं

ठेले पर स्कूटी-सिलेंडर रखकर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बंगले का घेराव करने जा रही थीं

भोपाल (नप्र)। मोहन सरकार के बजट में महिलाओं को महंगाई से कोई राहत नहीं मिलने के विरोध में आज महिला कांग्रेस ने भोपाल में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बंगले का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिला कार्यकर्ता संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया के नेतृत्व में जमा हुईं। इसके बाद ठेले पर स्कूटी और सिलेंडर रखकर मंत्री जगदीश देवड़ा के बंगले का घेराव करने नारेबाजी करते हुए निकलीं। इस बीच पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रेडक्रॉस हॉस्पिटल के पास रोक लिया।

पुतला दहन की कोशिश, पुलिस से झड़प

प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का पुतला जलाने की कोशिश की। पुलिस ने पुतला जलाने से रोका, जिसके बाद महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बन गई। महिलाओं का कहना था कि बजट में न तो रसोई गैस सस्ती हुई और न ही पेट्रोल-डीजल या घरेलू खर्चों पर कोई राहत दी गई।

नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय की ओर निकलीं महिलाएं

पुलिस को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद महिला कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय की ओर निकलीं। इस दौरान उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री के विरोध में नारे लगाए।

महिलाएं बोलीं-

इलाके में पानी के लिए जूझ रहे लोग

भोपाल के पंचशील नगर से प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। एक महिला ने कहा कि उनके इलाके में गंदा पानी आ रहा है, जिससे उसके तीनों बच्चे बीमार पड़ गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से आई दूसरी महिला, जो कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुई, ने बताया कि वह लोगों के घरों में बर्तन साफ कर गुजारा करती है। छत्तीसगढ़ में काम नहीं मिलने पर वह भोपाल आई, लेकिन यहां भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का पुतला जलाने की कोशिश- प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का पुतला जलाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बन गई।

हर्जाने की मांग-धमकियों से डरकर ऑटो चालक ने लगाई फांसी

सड़क हादसे के बाद 2 लाख की मांग पर 5 बच्चों के पिता ने जान दी

पन्ना (नप्र)। बृजपुर थाना क्षेत्र के उमरी गांव में एक ऑटो चालक ने आत्महत्या कर ली। सड़क हादसे के बाद 2 लाख रुपए की मांग और जान से मारने की धमकी से परेशान होकर फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान सुनील (27) आदिवासी के रुप में हुई। वह पांच बच्चों का पिता था। पुलिस के अनुसार, मृतक सुनील आदिवासी (पिता भूरा आदिवासी) बुधवार को पहाड़ी खेड़ा से यात्रियों को लेकर अपने गांव उमरी लौट रहा था। उमरी गैस एजेंसी के पास सामने से आ रही एक बाइक ने उसके ऑटो को टक्कर मार दी। परिजनों ने बताया कि बाइक चालक विकास लोधी कथित तौर पर नशे में था।

दो लाख की मांग, धमकियों से तनाव में दी जान- हादसे के बाद विकास लोधी ने सुनील पर 2 लाख रुपए के हर्जाने की मांग करते हुए दबाव बनाना शुरू कर दिया। पैसे न देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे सुनील गहरे मानसिक तनाव में आ गया था। समझौते की सभी कोशिशें विफल रहने के बाद, सुनील ने आज को अपने घर के एक खंभे से तौलिए का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

चाचा बोले- धमकियों से डरकर भतीजे ने लगाई फांसी

मृतक के चाचा नयनसुख ने बताया कि सुनील लगातार मिल रही धमकियों से डरा हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क हादसे को उगाही का जरिया बना लिया गया, जिसके कारण युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भोपाल-उज्जैन समेत 25 जिलों में बारिश

● श्योपुर में 1 इंच पानी गिरा, 63 किमी की रफ्तार से चली आंधी, कई जगह फसलें आड़ीं, सर्वे का आदेश

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया है। नए सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश में फरवरी के महीने में तीसरी बार ओले और बारिश का दौर शुरू हुआ है।

24 घंटे के दौरान भोपाल, उज्जैन समेत 25 जिलों में बारिश हुई। इनमें धार, श्योपुर, शिवपुरी, इंदौर, आगर-मालवा, राजगढ़, खरगोन, मुरैना, सीहोर, दतिया, ग्वालियर, गुना, रतलाम, बड़वानी, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, देवास, विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर जिले भी शामिल हैं।

श्योपुर के नालछा में सबसे ज्यादा 1 इंच पानी गिर गया। आंधी की रफ्तार 63 किमी प्रतिघंटा रही। भोपाल, सीहोर-आगर में 37 किमी, शाजापुर में 35किमी, गुना में 31 किमी, राजगढ़ में 30 किमी, धार, नीमच और शिवपुरी में 28 किमी गति दर्ज की गई।

दानों की गुणवत्ता और पैदावार पर बुरा असर- इस बेमौसम बारिश और तेज आंधी ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कई जिलों में खेतों में खड़ी फसलें आड़ी हो गई हैं, जिससे दानों की गुणवत्ता और पैदावार पर बुरा असर पड़ने की आशंका है।

कृषि मंत्री ने कहा- मिलेगा उचित मुआवजा

प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार इस संकट की घड़ी में उनके साथ है। बारिश और ओलों से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के अधिकारी प्रभावित खेतों का दौरा कर सर्वे करेंगे, ताकि नुकसान का सही आंकड़ा सामने आ सके। मंत्री कंसाना ने कहा, जहां-जहां भी ओलावृष्टि और तेज बारिश की वजह से फसलें आड़ी हुई हैं या दाने खराब हुए हैं, वहां नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया है कि सर्वे का काम पूरी पारदर्शिता के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि किसानों को राहत राशि मिलने में देरी न हो।

प्रदेश में खजुराहो सबसे ठंडा, न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज

प्रदेश में खजुराहो सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा राजगढ़ (10.0 डिग्री) और पचमढ़ी (10.2 डिग्री) में भी कड़ाके की ठंड महसूस की गई।

इन जिलों में हुई बारिश: मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, दतिया, गुना, ग्वालियर, इंदौर, रतलाम, श्योपुर, उज्जैन, धार, विदिशा, बड़वानी, आगर-मालवा, शाजापुर, मुरैना, छतरपुर, शिवपुरी, सीहोर और मंदसौर जैसे जिलों में बारिश दर्ज की गई है।